मनेन्द्रगढ़
13 फरवरी 2026 शुक्रवार

दैनिक
मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

कानपुर लैंबोर्गिनी कांड- अरबपति का बेटा गिरफ्तार

पिता की बचाने की कोशिशें नाकाम, नकली ड्राइवर तक पेश किया

कानपुर,एजेंसी। कानपुर में तेज रफ्तार लेम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा आखिरकार गिरफ्तार हो गया। DCP अतुल श्रीवास्तव ने कहा, लेम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को गुरुवार सुबह घर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

शिवम मिश्रा, आरोपी

पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और AJCM कोर्ट लेकर पहुंचीं। कोर्ट के बाहर वीडियो बनाने पर शिवम मीडियाकर्मी पर भड़क गया। इशारों में कहा- वीडियो क्यों बना रहे हो। दरोगा दिनेश कुमार ने कोर्ट में बताया- शिवम ने जांच में सहयोग नहीं किया। गुरुवार को सूचना मिली कि आरोपी एंबुलेंस से भाग रहा। खुद को छिपाए रखने के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है।

कोर्ट में पेशी के दौरान शिवम बीमार नजर आया। हाथ में वीगो लगी है। पुलिसवाले और रिश्तेदार उसे सहारा देते नजर आए। शिवम के साथ दिल्ली के एक फैमिली डॉक्टर भी हैं। कोर्ट के बाहर वीडियो बनाने पर शिवम मीडियाकर्मी पर भड़क गया। इशारों में कहा- वीडियो क्यों बना रहे हो।

तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा ने अपने इकलौते बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहे। 8 फरवरी को हादसे के तुरंत बाद पहले घटनास्थल से बेटे को हटवाया। फिर मीडिया से बातचीत में दावा किया- मेरा बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था।

अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार का दावा

लिखा- एअर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख का ऑफर दिया

लंदन/नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एअर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। लंदन के अखबार 'द इंडिपेंडेंट की एअर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई है।

इसके मुताबिक एअर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को अतिरिक्त मुआवजे के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है।

एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख की अंतिम राशि देकर समझौते की पेशकश कर रही है। कुछ मामलों में यह 20 लाख रुपए तक है।

परिवारों को यह शर्त माननी होगी कि वे भविष्य में हादसे से जुड़ा दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त करेंगे। यह छूट किसी भी देश या कोर्ट में लागू रहेगी।

लीगल टीम ने किया विरोध एअर इंडिया के इस प्रस्ताव का 130 पीड़ितों के परिवारों की लीगल टीम ने विरोध किया है। उसका कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई है। जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। ऐसे में केस का अधिकार छोड़ने को कहना अनुचित है। कुछ घायल परिवारों का इलाज भी अभी जारी है।इस मामले में एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि एअर इंडिया इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रहे हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। शुरुआती अं?तरिम राशि देने के बाद हमने यह तय किया है कि हर परिवार को दी जाने वाली आखिरी रकम सही और कानून के हिसाब से हो।

बेंगलुरु में इंजीनियर ने चाकू मारकर माता-पिता की हत्या की

स्टार्टअप के लिए पैसे देने से इनकार किया था; पिता रिटायर्ड नेवी अफसर, मां डेंटिस्ट थी

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में 33 साल के सॉफ्टवेयर इंजिनीयर ने चाकू मारकर अपने माता-पिता की हत्या कर दी। घटना बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। आरोपी का नाम रोहन चंद्र भट्ट है।

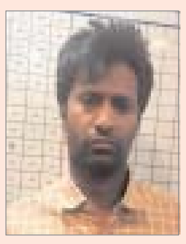

पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहन ने स्टार्टअप के लिए माता-पिता से पैसे मांगे थे। मना करने पर उसने दोनों को चाकू से मार डाला।

मृतकों की पहचान रिटायर्ड नेवी कैप्टन नवीन चंद्र भट्ट(60) और उनकी पत्नी डॉ. श्यामला भट्ट(55) जो कि पेशे से डेंटिस्ट थीं, के रूप में हुई है। हमले के बाद आरोपी दोनों को मणिपाल अस्पताल लेकर गया।

यूएन का दावा- दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश ने ली

हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की; रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र

नई दिल्ली, एजेंसी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने ली है।

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले पर एक कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी(NIA) कर रही है। एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया था।

रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है। जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकी भी मारे जा चुके हैं।

यह रिपोर्ट NSC की 1267 सैंक्शंस कमेटी को सौंपी गई है। कमेटी ISIS, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों पर नजर रखती है।

JeM ने बनाया महिला आतंकियों का संगठन

रिपोर्ट के मुताबिक जैश प्रमुख मसूद अजहर ने अक्टूबर 2025 को महिला आतंकियों की एक अलग विंग बनाई थी। इसका नाम जमात-उल-मुमिनात है। यह विंग आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। हालांकि ये विंग ह की लिस्ट में यह शामिल नहीं है।

रिपोर्ट में सदस्य देशों के अलग-अलग आकलन का भी जिक्र है। कुछ देशों ने माना कि छ्व्नरू आतंकी संगठन अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। वहीं कुछ देशों ने इसे निष्क्रिय बताया है।

पुणे में बंगाली मजदूर सुखन महतो की हत्या

मुख्यमंत्री ममता बोलीं- घृणात्मक अपराध; गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की

कोलकाता, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे भाषा और पहचान के आधार पर होने वाला घृणात्मक अपराध बताया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि वे इस क्रूर हत्या से स्तब्ध और गुस्से में हैं। बता दें कि 24 वर्षीय मृतक सुखन महतो बंगाल के पुरुलिया जिले के बंडवान के रहने वाले थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे।

ममता बनर्जी ने कहा कि एक युवक को उसकी भाषा, पहचान और जड़ों के कारण मारा गया। सीएम ने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह घृणात्मक अपराध सीधे उस माहौल का नतीजा है, जिसमें विदेशियों और अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ झूठे भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की।

असम से 16 घुसपैठियों को वापस भेजा गया बांग्लादेश

गुवाहाटी, एजेंसी। असम में घुसे 16 घुसपैठियों को बीती रात बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व में विपक्षी सरकार वोट बैंक के स्वार्थ में पिछले दरवाजे से अनजान लोगों को असम में घुसपैठ करने की सुविधा प्रदान करती थी।

आज असम सरकार राज्यवासियों के अस्तित्व सुरक्षा की खातिर अनजान घुसपैठियों के विरूद्ध परी तरह से कदम उठा रही है। यह आज सभी के सामने है। हमारे इसी कदम के चलते बीती रात असम में अवैध रूप से घुसे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस उनके देश भेज दिया गय है।

उल्लेखनीय है कि असम से लगने वाली बांग्लादेश की सीमा पर जहां बीएसएफ के जवान सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहीं असम पुलिस भी किसी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी ओर से हर संभव कदम उठा रही है।

भाजपा सांसद का नोटिस-राहुल की सदस्यता खत्म हो

कहा- वे देश को गुमराह कर रहे; रिजिजू ने स्पीकर चैंबर में हंगामे का वीडियो जारी किया

नई दिल्ली, एजेंसी। बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे के कारण नहीं चल सका। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। नारेबाजी भी होती रही।

स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट के बाद ही सदन को स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। उधर, पीएम मोदी आज राज्यसभा में पहुंचे थे।

इधर, BJP सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने लाइफटाइम बैन लगाने की मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन वह प्रपोजल है, जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। इस मोशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। न्यूज एजेंसी ढ्ढ्रस्न ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी। हालांकि, 11 फरवरी के उनके भाषण के कुछ हिस्से हटा दिए जाएंगे।

इससे पहले, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने ङ्ग पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है। उन्होंने किसी को नहीं उकसाया। वे चुपचाप थीं। आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी।

मदनी बोले-वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला

ये मनमाना और एकतरफा; वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन

नई दिल्ली, एजेंसी। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है।

संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने ङ्ग पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद

मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे।

वायु सेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल जेट्स खरीदने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

सीसीएस से अंतिम मंजूरी के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे पर डील होगी पक्की

नई दिल्ली, एजेंसी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से पहले केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद वायु सेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसमें 18 विमान सीधे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से निर्मित होकर भारत आएंगे। शेष 96 विमान भारत में निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बनाए जाएंगे। इनमें से कई ट्विन-सीटर ट्रेनिंग वर्जन भी होंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) से गुरुवार को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) मिलने के बाद व्यावसायिक वार्ता शुरू होगी, फिर अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) देगी।

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज डीएसी की बैठक साउथ ब्लॉक में हुई, जिसमें सशस्त्र सेनाओं के लिए कई अहम फैसले हुए। केंद्र ने फ्रांस के साथ सरकार से सरकार सौदे के तहत वायु सेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। इन विमानों में 40-50 फीसदी मेक इन इंडिया हथियारों को इंटीग्रेट करने का पूरा अधिकार होगा। फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ रुपये का यह सैन्य हार्डवेयर सौदा किसी भी देश के साथ अब तक हुए अनुबंध से कम से कम पांच गुना बड़ा है। भारत के पास अभी 36 राफेल हैं और इस सौदे से 150 विमान हो जाने पर देश की हवाई ताकत कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने एक दिन पहले ही प्रेस कांफ्रेंस में बताया था कि ऑपरेशन %सिंदूर% के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया, जिसमें राफेल एक %हीरो% था। अब इस सौदे के लिए मंजूरी मिलने के बाद भारत के पास कुल राफेल ऑर्डर 186 जेट्स हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम का 63 हजार करोड़ का पहले ही ऑर्डर दिया जा चुका है। भारत में लगभग 100 जेट्स बनाए जाएंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डसॉल्ट-टाटा पार्टनरशिप और मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इनकी डिलीवरी 2030 तक होने की उम्मीद है

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 16 जनवरी को ही फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देगी। इसके बाद यह डील इसी माह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे पर पक्की हो जाएगी। वायु सेना के अंबाला एयरबेस पर पहले से ही राफेल फ्लाइट-ट्रेनिंग और मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा चालू है। ये जेट्स 'मेक इन इंडिया' स्कीम के तहत खरीदे जाएंगे, जिसमें राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय फर्म के साथ साझेदारी करेगी।

मोदी आज नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे

सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन नॉर्थ-साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस 'सेवा तीर्थ' में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी ह्द्ब के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे 'सेवा तीर्थ' बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में PMO और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है।

इन दोनों इमारतों को 105 सालों से देश की सत्ता का केंद्र माना जाता रहा है। यहां 1921 से सरकारी विभागों का कामकाज चल रहा है।

नोएडा एयरपोर्ट का होगा सुपरफास्ट विस्तार

नोएडा एयरपोर्ट का होगा सुपरफास्ट विस्तार, यूपी बजट में सरकार ने खोला खजाना

नोएडा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में बुधवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण में होने वाले विकास कार्यों के लिए 750 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा हुई। 700 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण और 50 करोड़ रुपये भवन निर्माण के लिए आवंटित किए गए। इससे जेवर में जल्द शुरू होने जा रहे एयरपोर्ट के विस्तार का काम और रफ्तार पकड़ेगा। उधर, गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना पर भी काम तेज होगा।

किसान जमीन देने को तैयार : नोएडा एयरपोर्ट से अगले कुछ माह में व्यावसायिक विमानों की उड़ानें प्रस्तावित हैं। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांव की 1888.98 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। 4300 रुपये प्रतिकर से मुआवजे की घोषणा के बाद किसान जमीन देने को तैयार हैं।

पहले चरण का काम पूरा : प्रथम चरण में 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूरा हो चुका है। पहले चरण में कुल 4588 करोड़ की लागत आई है। वहीं, दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। परियोजना के तीसरे और चौथे चरण में कुल 2053 हेक्टेयर भूमि चाहिए। इनमें से 14 गांव की 1888.98 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। शेष भूमि प्रशासन के पास पहले से है।

पुनर्वास केंद्र बनाने का रास्ता साफ: नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापित होने के वाले परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन केंद्र का रास्ता साफ हो गया ।

दूसरा रनवे बनेगा : परियोजना के तहत दूसरे चरण में 490 एकड़ में दूसरा रनवे बनेगा। इसके अलावा सर्विस रनवे बनेगा और 800 एकड़ में एविएशन इंडस्ट्री लगेगी। एयरपोर्ट परिसर में 2053 हेक्टेयर में दो रनवे और 750 एकड़ में विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी स्थापित होगी।

हरनंदीपुरम को फंड की कमी नहीं: उत्तर प्रदेश के बजट से गाजियाबाद में बन रही नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को रफ्तार मिलेगी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह टाउनशिप इसी योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही है। ऐसे में अब योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाने की योजना पर काम हो रहा है।

स्मार्ट सिटी के काम में तेजी आएगी : बजट में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को बड़ी सौगात मिली है। इसमें गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर समेत अन्य निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नगर निगम गाजियाबाद पहले से ही राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल है। निगम ने राज्य स्मार्ट सिटी के तहत शहर में पहले भी कई कार्य कराए हैं। इनमें शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 41 स्थान पर लगभग 800 आधुनिक कैमरे लगाए हैं।

असम में संदिग्ध मतदाताओं के लाखों नाम हटाए गए : सीएम हिमंत

गोवाहाटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि राज्य में चुनावी मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण (एसआर) के दौरान लाखों संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, यह केवल शुरुआत है। जब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) किया जाएगा, तो और भी लोगों के नाम हटाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सरमा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन हटाए गए नामों में से कई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर थे। यह टिप्पणी उस दिन आई है जब चुनाव आयोग ने असम के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की, जिसमें 2.43 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं।

उन्होंने कहा, जितना संभव हो, हमारे पार्टी के सदस्यों ने शिकायतें दर्ज कीं। इन शिकायतों के आधार पर नाम हटाए गए हैं। सरमा ने दावा किया कि असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए गए। कुछ लोगों ने हमें धमकाने की कोशिश की। लेकिन हम सफल रहे। हमारे भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर के अधिकारियों को यह समझाने में सफल रहे कि जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं, वे अब निवासी नहीं हैं।

उन्होंने कहा, अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। शिकायतों और आपत्तियों के अंत में अंतिम चुनावी सूची मंगलवार को प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 2.49 करोड़ मतदाता हैं, जो ड्राफ्ट सूची से 0.97 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

सीएम ने पहले संकेत दिया था कि केवल मिया (स्थानीय भाषा में अवैध बांग्लादेशी मुसलमान) को एसआर प्रक्रिया के दौरान नोटिस दिए जा रहे थे, ताकि उन्हें दबाव में रखा जा सके और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पांच लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं।

छत्तीसगढ़ में दसवीं के छात्र को 100 उठक-बैठक कराई, हालत बिगड़ने पर अस्पताल रेफर

रायगढ़ , एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शारीरिक दंड का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पिछले महीने दसवीं कक्षा के एक छात्र को सजा के रूप में 100 बार उठक-बैठक करने के लिए कहा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तबीयत बिगड़ गई। छात्र को चलने-फिरने में कठिनाई हो रही है और वर्तमान में उसकी फिजियोथैरेपी चल रही है। उसे रायपुर के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू ने शिक्षिकाओं को नोटिस भेजा है, उनके जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। छात्र के स्वजन ने शिक्षिकाओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और प्रशासन से जांच की मांग की है।

3 घंटे चली नेतन्याहू संग बैठक

खत्म होने पर ट्रंप बोले- ईरान के साथ जारी रहेगी बातचीत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील समेत कई दूसरे गंभीर मुद्दों पर डिटेल में बातचीत हुई।

ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी : मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर डील पर ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल किसी भी मुद्दे पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

खास मुद्दों पर बातचीत : इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खास तौर पर ईरान मुद्दे और दूसरे क्षेत्रीय हालात पर बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे।

दोनों नेताओं के बीच हुई इस लंबी बातचीत को अंतराष्ट्रीय स्तर पर बहुत जरूरी माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा,मैंने अभी-अभी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनके कई रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग खत्म की है।

यह बहुत अच्छी मीटिंग थी, हमारे दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त रिश्ते बने हुए हैं। कोई पक्की बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि मैंने ज़ोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहे ताकि यह देखा जा सके कि डील हो सकती है या नहीं।

अगर हो सकती है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया है कि यह उनकी पसंद होगी। अगर नहीं हो सकती, तो हमें बस यह देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। पिछली बार ईरान ने तय किया था कि उनके लिए डील न करना ही बेहतर है, और उन्हें मिडनाइट हैमर से चोट लगी थी – यह उनके लिए ठीक नहीं रहा। उम्मीद है कि इस बार वे ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार होंगे।

इसके अलावा, हमने गाज़ा और आम तौर पर इस इलाके में हो रही ज़बरदस्त तरक्की पर भी बात की। मिडिल ईस्ट में सच में शांति है।

इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद! गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन जहां ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की बात कर रहा है, वहीं प्रशासन द्वारा ओबामा की क्लाइमेट पॉलिसी को रद्द करने जैसे कई दूसरे बड़े फैसले भी ले रहा है।

कनाडा के स्कूल गोलीकांड में आरोपी की पहचान

ओटावा, एजेंसी। कनाडा की पुलिस ने मंगलवार को हुए भयावह स्कूल गोलीकांड के आरोपी की पहचान कर ली है। जांच में सामने आया है कि हमला करने वाली एक 18 साल की महिला थी, जो लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम जेसी वैन रूटसेलार था। गोलीबारी के बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कनाडा के प्रशांत प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के दूरदराज इलाके टम्बलर रिज में स्थित एक स्कूल में हुई थी।

मौतों की संख्या संशोधित कर 9 की गई : शुरुआत में पुलिस ने 10 लोगों की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में जांच के बाद मृतकों की संख्या घटाकर 9 कर दी गई। पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि शुरुआती आंकड़े में गलती कैसे हुई, लेकिन पुष्टि की कि कुल नौ लोग मारे गए हैं।

परिवार के घर पर पहले भी पुलिस गई थी : ब्रिटिश कोलंबिया में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ड्वेन मैकडोनाल्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस पहले भी आरोपी के घर जा चुकी थी। उन्होंने कहा,हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि इस परिवार के घर पर पहले भी कई बार पुलिस को बुलाया गया था। इनमें से कुछ मामलों का संबंध मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से था। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या उन शिकायतों का सीधे तौर पर स्कूल हमले से संबंध था।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान : घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने इसे भयानक और दिल दहला देने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह कनाडा के इतिहास के सबसे दुखद दिनों में से एक है और देश मिलकर इस त्रासदी से उबरने की कोशिश करेगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

कनाडा में बंदूक कानून कड़े, फिर भी हमला हुआ : यह गोलीकांड कनाडा के इतिहास के सबसे घातक स्कूल हमलों में से एक माना जा रहा है।

ईरान पर हमले की तैयारी,पेंटागन मध्य-पूर्व में दूसरा विमानवाहक युद्धपोत भेजेगा

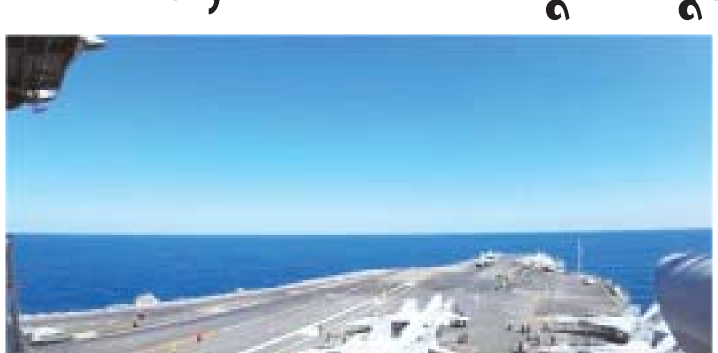

वॉशिंगटन, एजेंसी। एक अमेरिकी अखबार ने बुधवार को तीन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पेंटागन ने एक और विमानवाहक युद्धपोत स्ट्राइक ग्रुप को मध्य-पूर्व में तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय हुई जब ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ी हुई है और वॉशिंगटनङ्कतेहरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत चल रही है।

ट्रंप ने क्या कहा : मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के साथ बातचीत असफल होती है, तो वह मध्य-पूर्व में दूसरा विमानवाहक युद्धपोत भेजने पर विचार कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की जा सके। अखबार ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि यदि अंतिम आदेश मिलता है, तो युद्धपोत को रवाना करने का फैसला कुछ ही घंटों में लिया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि अभी तक ट्रंप ने औपचारिक रूप से तैनाती का आदेश नहीं दिया है और हालात बदलने पर योजना में बदलाव भी हो सकता है।

कौन सा युद्धपोत जाएगा : अगर दूसरा युद्धपोत भेजा गया, तो वह पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ शामिल होगा, जो पहले से ही मध्य-पूर्व में तैनात है। एक अधिकारी ने बताया कि पेंटागन अगले दो हफ्तों के भीतर एक और विमानवाहक युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है, जो संभवतः अमेरिका के पूर्वी तट से रवाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश इस समय वर्जीनिया के तट के पास सैन्य अभ्यास कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अपने अभ्यास को जल्दी खत्म कर सकता है।

ट्रंप–नेतन्याहू की लगभग 3 घंटे लंबी बैठक : व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात करीब तीन घंटे चली। बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर लिखा कि कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने लिखा- बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। मैंने साफ कहा कि ईरान से बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि समझौता संभव है या नहीं। अगर समझौता हो सकता है तो मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो परिणाम अलग होंगे। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी, पिछली बार जब ईरान ने समझौता नहीं किया था, तो उसे 'मिडनाइट हैमर' का सामना करना पड़ा था और यह उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उम्मीद है कि इस बार ईरान ज्यादा समझदारी दिखाएगा।

ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं : नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इजरायल या यूरोप पर हमला करने के लिए अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही क्षेत्रीय मिसाइल क्षमता मौजूद है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान अभी भी आम नागरिकों और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दे रहा है, जबकि उसने अमेरिका से ऐसा न करने का वादा किया था।

अगर बातचीत टूट गई तो क्या होगा : दोनों नेताओं ने इस पर भी चर्चा की कि अगर ईरान से बातचीत पूरी तरह टूट जाती है तो क्या होगा। इसमें – संभावित सैन्य कार्रवाई, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, इजरायल पर विचार किया गया।

खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर हाथी ने हमला किया, घायल

हरिद्वार, एजेंसी। वन विभाग की हरिद्वार रेंज स्थित बिशनपुर कुंडी गांव के पास एक बुजुग ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया। ग्रामीण बुधवार की देर शाम अपने खेत से लौट रहा था, उसी दौरान उसके सामने विशालकाय हाथी आ धमका और अचानक हाथी ने ग्रामीण को उठाकर पटक दिया। हादसे में बुजुर्ग के पैर की हड्डियां टूट गई। हरिद्वार के मिस्सरपुर, जगजीतपुर, जियापोता, जमालपुर समेत कई गांव हैं, जहां वर्षो से जंगली हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। वर्षो से इस समस्या का निदान नहीं हो सका है। बीते दिन बिशनपुर कुंडी गांव के पास एक बुजुर्ग ग्रामीण धर्मपाल निवासी पुरानी कुंडी,अपने खेत में रखवाली के लिए गया था। वापस लौटते समय वहां जंगली हाथी आ धमके, हाथियों को ग्रामीणों द्वारा खदेड़ा जा रहा था। इस दौरान सामने आये बुजुर्ग को हाथी ने उठाकर पटक दिया। हाथी के हमले में बुजुर्ग के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई। सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह तुरंग टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार वन विभाग की एसडीओ पूनम कैंथोला भी जिला अस्पताल पहुंची और घायल बुजुर्ग का हालचाल जाना। बुजुर्ग के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल बुजुर्ग को कनखल के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि ग्रामीण पर हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और टीम द्वारा ही ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल ग्रामीण को परिजन निजी अस्पताल में ले गए हैं,जहां उनका इलाज चल रहा है। विभाग की ओर से तत्काल पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की गई है। प्रावधान के अनुसार बाकी की धनराशि भी जल्द ही प्रदान की जाएगी।-

नोएडा बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब

नोएडा, एजेंसी। यूपी सरकार के बजट में कहा कि देश के 65 प्रतिशत मोबाइल का उत्पादन उत्तरप्रदेश में हो रहा है। मोबाइल उत्पादन में गौतमबुद्ध नगर पूरे देश में पहले नंबर पर है। देश के 55 फीसदी से अधिक मोबाइल फोन यहीं बनते हैं।

इन कंपनियों के फोन नोएडा में बन रहे : सैमसंग का यहां सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट है, जो सालाना 12 करोड़ यूनिट तक उत्पादन क्षमता रखता है। ओप्पो, वीवो, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी अन्य कंपनियां भी यहां पर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने को जीएसटी से भरने में गौतमबुद्ध नगर जिले का योगदान सबसे अधिक है।

मेक इन इंडिया का सपना हो रहा साकार : जानकारी के मुताबिक, सैमसंग के गौतमबुद्ध नगर स्थित संयंत्र में दुनिया के लगभग 25 फीसदी फोन का निर्माण होता है। मोबाइल फोन के निर्माण के साथ ही यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र होने के कारण यह क्षेत्र मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है।

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : यमुना सिटी के सेक्टर-24ए में वीवो कंपनी मोबाइल बना रही है। कंपनी को 169 एकड़ भूमि का आंवटन वर्ष 2018 में हुआ था। इसमें 156.32 एकड़ भूमि के लिए चेकलिस्ट जारी की गई थी। प्रथम चरण में कंपनी प्रति वर्ष छह करोड़ स्मार्ट मोबाइल तैयार कर रही है। दो चरणों में कंपनी का निर्माण पूरा होगा। दूसरा चरण पूरा होने के बाद शहर में हर साल करीब 14.40 करोड़ मोबाइल का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में यहां पर 800 लोग काम कर रहे हैं। दूसरा चरण पूरा होने के बाद एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहां की मोबाइल कंपनियों ने निर्यात का ग्राफ बढ़ाने के साथ जीएसटी चुकाने में भी टॉप रैंक हासिल की है। जीएसटी महकमे ने राज्य जीएसटी देने वाली जिन टॉप 100 कंपनियों की सूची जारी की थी, उसमें सबसे ऊपर ग्रेटर नोएडा की ओप्पो मोबाइल कंपनी का नाम है। वर्ष 2023-24 में ओप्पो मोबाइल इंडिया ने 1945. 87करोड़ रुपये जीएसटी जमा किया था। वर्ष 2024-25 में 1141.47 करोड़ रुपये जीएसटी जमा किया था।

महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, 191 किलो मीटर दूर बॉडी को लगाया ठिकाने

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के साथ 191 द्मद्व गाड़ी चलाने का आरोप है। आरोपी पुलिस वाले को कलंबोली इलाके के एक आदमी पर शक था। कथित तौर पर आदमी की हत्या करने के बाद, उसने बॉडी को अपनी कार की बगल वाली पैसेंजर सीट पर रखा और उसे महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोनांद ले गया, जो लगभग 191 किलोमीटर दूर है। जब वह अपनी जगह पर पहुंचा, तो उसने बॉडी को कुएं में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने सतारा के एक गांव सुखेड़ के पास एक कुएं से थोड़ी जली हुई बॉडी बरामद की। टेक्निकल जांच और सबूतों के आधार पर, आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी हत्या की जांच कर रही है।

कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार लेकिन सत्ता में साझेदारी की कोई गुंजाइश नहीं : स्टालिन

चैन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने द्रमुक और कांग्रेस के बीच किसी तरह की दरार की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए बुधवार को कहा कि गठबंधन पूरी तरह से कायम है। स्टालिन ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाए जा रहे संभावित गठबंधन सरकार के सवाल को भी खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भ्रम नहीं है।

सरकार में सत्ता को साझा करना तमिलनाडु को नहीं भाता है। कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है। द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग केवल गठबंधन में फूट डालने के लिए सत्ता-साझा करने का मुद्दा उठा रहे हैं। यह चाल काम नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में भ्रम की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं।

नवोदय विद्यालय चुरहट में 'फुटबॉल फॉर स्कूल' कार्यक्रम का आयोजन, शिक्षा और खेल के सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। पीएम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में 'फुटबॉल फॉर स्कूल' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के चयनित 140 विद्यालयों को विधायक रीती पाठक के हाथों फुटबॉल वितरित किए गए इस अवसर पर पाठक ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया अपने संबोधन में विधायक रीती पाठक ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा, 'फुटबॉल फॉर स्कूल जैसे कार्यक्रम बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करते हैं विधायक ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने का आह्वान किया उन्होंने यह भी कहा कि खेल बच्चों को मानसिक संतुलन सकारात्मक सोच और लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देते है पाठक ने नवोदय विद्यालय परिवार और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराना एक सराहनीय कदम है इस पहल से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करें ताकि वे शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त नागरिक बन सकें कार्यक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार के कमिश्नर राजेश लखानी, नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों, जिला कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, उप आयुक्त आर.के. वर्मा, सहायक आयुक्त डी.के. सिंह और डॉ. जरीना कुरैशी ने मार्गदर्शन किया विद्यालय प्राचार्य डॉ. डी.के. त्रिपाठी ने विद्यालय के उन्नयन एवं विकास की जानकारी दी कार्यक्रम में विद्यालय के कप्तान मास्टर हर्षित द्विवेदी और छात्रा कप्तान कु. अनुपमा द्विवेदी ने विद्यालय की उपलब्धियों और समग्र विकास पर प्रकाश डाला सांस्कृतिक कार्यक्रम में मां सरस्वती वंदना और स्वागत गान ने उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया कार्यक्रम का सफल संचालन जिला शिक्षा अधिकारी पी.के. सिंह और प्रवीण कुमार मिश्रा की विशेष सहभागिता से हुआ।

काम ले रहे ज्यादा वेतन मिल रहा कम कई संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। गुरुवार को कई कर्मचारी और श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया उन्होंने कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा प्रदर्शन में आंगनवाड़ी एवं सहायिका कार्यकर्ता यूनियन, चौकीदार भृत्य संघ, मजदूर संगठन और सीमेंट प्लांट श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए इन संगठनों ने आरोप लगाया कि उनसे अत्यधिक काम लिया जा रहा है लेकिन पारिश्रमिक और सुविधाएं न्यूनतम स्तर पर हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की प्रतिनिधि रश्मि सोनी ने बताया कि कार्यकर्ताओं पर लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं नियमित कार्यों के अलावा उनसे बीएलओ का काम भी करवाया जा रहा है जिसके लिए उन्हें उचित भुगतान नहीं मिलता उन्होंने बीएलओ के कार्य से मुक्ति और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग की कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारी चौकीदार भृत्य संघ के प्रतिनिधि रामप्रताप लुनिया ने चौकीदारों की दयनीय स्थिति का उल्लेख किया उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर उन्हें आज भी मात्र ?500 मासिक वेतन पर काम करना पड़ रहा है जबकि उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं उन्होंने समय पर वेतन भुगतान की भी मांग की मजदूर संगठन के मनोज कोल ने मजदूरी दरों में वृद्धि और सरकारी सुविधाओं की मांग की उन्होंने ग्राम पंचायतों में कई कार्यों के केवल कागजों में पूरे दिखाए जाने की बात कही सीमेंट प्लांट श्रमिक यूनियन के विजय परस्ते ने अल्ट्राटेक और जेपी सीमेंट प्लांट सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिकों की छुट्टी, पारिश्रमिक और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा उन्होंने कहा कि काम अधिक लिया जाता है लेकिन सुविधाएं और वेतन संतोषजनक नहीं हैं संबंधित विभागों को भेजेंगे मांग पत्र इस संबंध में कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी ने बताया कि सभी संगठनों के ज्ञापन प्राप्त कर लिए गए हैं।

अस्पताल खड़ी एंबुलेंस में आग तेज धमाके के बाद धू-धू कर जली गाड़ी फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

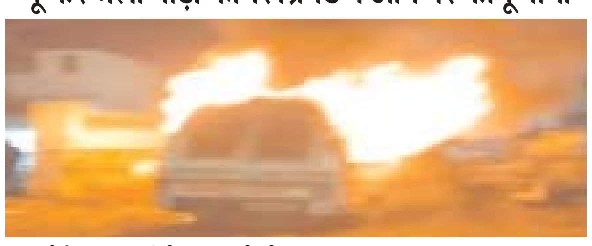

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला अस्पताल परिसर में बुधवार रात करीब 10 बजे खड़ी एक एंबुलेंस में भीषण आग लग गई आग लगने से पहले एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी जिसके बाद एंबुलेंस देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके के कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम जिला अस्पताल पहुंची लेकिन तब तक एंबुलेंस लगभग पूरी तरह जल चुकी थी फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया उनकी तत्परता से आसपास खड़े अन्य वाहनों और अस्पताल परिसर को संभावित नुकसान से बचाया जा सका इस घटना के दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया मरीजों के परिजन और अस्पताल स्टाफ आग की लपटों और धुएं को देख चिंतित नजर आए हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है।

नगर निगम रीवा के विशेष वसूली शिविरों में करदाताओं की बढ़ी सहभागिता पुराना बस स्टैण्ड शिविर में 4.58 लाख से अधिक की वसूली, आज नीम चौराहा में शिविर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम रीवा द्वारा राजस्व वसूली अभियान को गति दी जा रही है निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर 09 फरवरी से 02 मार्च 2026 तक वार्डवार विशेष वसूली शिविरों का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों का उद्देश्य सम्पत्तिकर, जलकर एवं अवैध कॉलोनी शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना है शिविर का समय प्रतिदिन प्रात: 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है इसी क्रम में 12 फरवरी को वार्ड क्रमांक 6 एवं 18 के लिए पुराना बस स्टैण्ड परिसर में विशेष वसूली शिविर आयोजित किया गया शिविर में करदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बकाया करों का भुगतान किया प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर में सम्पत्तिकर की बकाया राशि 2,74,143 रुपये तथा जलकर की बकाया राशि 1,83,866 रुपये जमा कराई गई इस प्रकार एक ही दिन में कुल 4,58,009 रुपये की राजस्व वसूली की गई, जिसे नगर निगम प्रशासन ने संतोषजनक बताया है नगर निगम प्रशासन ने बताया कि इन विशेष शिविरों का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को उनके वार्ड में ही सरल एवं सुविधाजनक तरीके से कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराना है शिविरों में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर नागरिकों को कर संबंधी जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं तथा लंबित बकाया राशि की गणना कर त्वरित रसीद जारी की जा रही है अगले चरण में 13 फरवरी को वार्ड क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए नीम चौराहा बोदाबाग में विशेष वसूली शिविर आयोजित किया जाएगा नगर निगम द्वारा वार्डवार इस प्रकार के शिविरों का निरंतर आयोजन किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक नागरिक समय रहते अपने करों का भुगतान कर सकें और अंतिम समय की भीड़ से बच सकें गौरतलब है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर निगम द्वारा आवासीय भवनों पर सम्पत्तिकर में 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जा रही है निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया करों का शीघ्र भुगतान करें नगर निगम ने कहा है कि करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर के विकास कार्यों-जैसे सड़क, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं-के सुदृढ़ीकरण में किया जाता है अत: नगरवासी शिविर में पहुंचकर अपने करों का भुगतान करें और नगर के समग्र विकास में सहभागी बनें।

अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, पुलिस ने पकड़ा; वाहन मालिक पर भी होगी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है इसी कड़ी में गुरुवार को सरई पुलिस ने ग्राम जमगड़ी रेलवे पुल के पास से अवैध रूप से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सरकारी खनिज संपदा की रेत का अवैध उत्खनन कर निजी फायदे के लिए परिवहन कर रहे हैं सूचना के आधार पर सरई पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और बिना नंबर का नीले रंग का सोनालिका कंपनी का ट्रैक्टर पकड़ लिया, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध रेत लदी हुई थी जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि रेत की कीमत करीब 5 हजार रुपए बताई गई है पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर के मालिक के खिलाफ भी साक्ष्यों के आधार पर अलग कार्रवाई की जाएगी साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजसात करने के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

गर्ल्स कॉलेज में कार्यक्रम पर विवाद, एनएसयूआई ने सवाल उठाए प्राचार्य बोले- भाजपा के कार्यक्रम की नहीं थी जानकारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 10 फरवरी 2026 को आयोजित 'युवा संवाद/बजट 2026' कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम को नियमों के विरुद्ध बताते हुए महाविद्यालय प्रशासन से स्पष्टीकरण और कार्रवाई की मांग की है एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने छात्राओं के साथ मिलकर गुरुवार को एक ज्ञापन सौंपा उन्होंने आरोप लगाया कि गर्ल्स कॉलेज जैसे संवेदनशील शैक्षणिक संस्थान में किसी राजनीतिक संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व लिखित अनुमति और स्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया कॉलेज के गेट पर एनएसयूआई कार्यकर्ता परिहार ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए न तो विधिवत अनुमति ली गई और न ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गईं उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति/आदेश की प्रति, आवेदन व पत्राचार, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश रजिस्टर पुलिस प्रशासन को दी गई सूचना, सुरक्षा व्यवस्था का विवरण और कार्यक्रम की जिम्मेदारी तय करने संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है मामले के तूल पकड़ने के बाद कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ओपी नामदेव ने अपनी सफाई दी है। प्राचार्य नामदेव ने बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चा से संबंधित है उनके अनुसार, 9 फरवरी की शाम को उन्हें मौखिक रूप से बताया गया था कि यह विधायक रीति पाठक का कार्यक्रम है इसी आधार पर उन्होंने मौखिक अनुमति दी थी जबकि लिखित रूप से कोई अनुमति जारी नहीं की गई थी प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि उन्हें कार्यक्रम के किसी पार्टी विशेष से संबंधित होने की जानकारी नहीं थी।

तालाब में डूबने से युवक की मौत चाची की अस्थि-विसर्जन करने आया था युवक

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के मड़वास थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है पथरौला पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सिलवार में फूलमती देवी मंदिर के पास बने तालाब में अस्थि-विसर्जन के दौरान 22 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई गुरुवार को युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान तेजभान साहू उर्फ संजू (22) पिता देवराज साहू के रूप में हुई है वह अपनी चाची के निधन के बाद अस्थि-विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने परिवार सहित तालाब पहुंचा था चाची की मौत चार दिन पहले हुई थी और तीसरे दिन की रस्म के लिए करीब 100 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे कार्यक्रम के दौरान तेजभान अन्य परिजनों के साथ तालाब में स्नान करने उतरा इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी की ओर चला गया और डूबने लगा मौके पर मौजूद परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचाने का तुरंत प्रयास किया कई लोग तालाब में कूदे लेकिन तेजभान का कोई सुराग नहीं मिल सका स्थिति गंभीर होते देख परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया इसके बाद स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स की टीम को बुलाया गया टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे की सर्चिंग की देर शाम युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया।

एनसीएल खदानों में हड़ताल कोयला उत्पादन और डिस्पैच ठप, श्रमिकों ने ट्रेनों के सामने किया प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड के विरोध में 12 फरवरी को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर गुरुवार को जिले में देखा गया नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की सभी कोयला परियोजनाओं में सुबह से ही श्रमिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया जिससे कोयला उत्पादन और डिस्पैच व्यवस्था प्रभावित हुई इस हड़ताल के कारण एनसीएल की कोयला खदानों से कोयले की ढुलाई पर गहरा असर पड़ा कई परियोजनाओं में कोयले का डिस्पैच आंशिक रूप से ठप हो गया ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले श्रमिकों ने छप क्षेत्र में कोयला ले जाने वाली ट्रेन के सामने प्रदर्शन किया, जिससे रेल परिवहन भी बाधित हुआ जयंत, निगाही और अम्लोरी सहित एनसीएल की सभी 11 कोल इंडिया परियोजनाओं में यह आंदोलन जारी है प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने लेबर कोड वापस लेने रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मजदूर हितों की रक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की परियोजना क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित रहा और कई स्थानों पर मशीनें बंद रहीं ट्रेड यूनियनों के नेताओं का कहना है कि नए लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं रोजगार की स्थिरता समाप्त हो रही है और निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण 19 एवं 20 फरवरी को

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में 19 एवं 20 फरवरी 2026 को दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशानुसार इस प्रशिक्षण के आयोजन के निर्देश जारी किए हैं जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षण प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों, विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकार तथा धारा 3(1) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों की मान्यता पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी यह प्रशिक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के लिए आयोजित किया जा रहा है प्रशिक्षण में श्री कमल किशोर आर्मो, सार्थक त्यागी, श्री सत्यशोभन दास एवं लखन मरावी मास्टर ट्रेनर के रूप में मार्गदर्शन देंगे प्रथम दिवस 19 फरवरी को विभिन्न उपखण्डों के प्रशासनिक अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की सहभागिता रहेगी द्वितीय दिवस 20 फरवरी को जनपद सदस्यों सहित अन्य अशासकीय सदस्य प्रशिक्षण में शामिल होंगे, जिनमें प्रदीप कुमार सिंह, संतोष सिंह गोड, देववत सिंह, माया कोल, केमलभान सिंह, हीरा कुमार सिंह, शिवभान सिंह, श्रीमती रानू सिंह, दीपक कोल, वंदना सिंह, मुन्ना कोल, सम्पूर्ण सिंह, अतिबल सिंह, भानू प्रताप सिंह एवं सावित्री पनिका सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में श्री एस.डी. सोनवानी (एसडीओ वन सीधी), श्री राजेश पारस (नायब तहसीलदार मड़वास), धनंजय मिश्रा (अति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी), सूर्यप्रताप सिंह, बृजेन्द्र कुमार बुनकर, रजनीश मिश्रा, लालता केवट एवं कृष्णपाल सिंह को नामांकित किया गया है प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की गहन समझ विकसित करना, सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना तथा समुदाय आधारित संरक्षण-प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करना है।

जनगणना में जाति कॉलम जोड़ने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी महासभा का प्रदर्शन, बैकलॉग भर्ती शुरू करने व 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्ति की मांग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा के नेतृत्व में मंगलवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा प्रदर्शन के दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने जनगणना में पिछड़ा वर्ग की जाति का पृथक कॉलम जोड़े जाने लंबित बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखने के निर्णय को समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई महासभा के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग की जातियों का पृथक कॉलम जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सामने आ सकें और उसी अनुपात में नीतियां एवं योजनाएं बनाई जा सकें उनका कहना था कि बिना सटीक आंकड़ों के सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहती है इसके साथ ही संगठन ने देश एवं प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लाखों रिक्त स्थायी शासकीय पदों पर लंबित बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से पद रिक्त पड़े हैं जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है और शासन की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है बैकलॉग भर्ती शुरू होने से योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी महासभा ने मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियों में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों के 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखने के निर्णय को अन्यायपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति न मिलना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है संगठन ने मांग की कि होल्ड पर रखे गए पदों पर तत्काल नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं वक्ताओं ने यूजीसी एक्ट को और अधिक प्रभावी बनाकर कड़ाई से लागू करने की भी मांग की, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशव्यापी एवं देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और समाज के साथ हो रही कथित नाइंसाफी को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा प्रदर्शन के दौरान पुष्पराज सिंह, डॉ. रजनीश सिंह, राकेश यादव, जेपी कुशवाहा, छोटेलाल रजक सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की महासभा ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

फर्जी की मर्जी पर अंकुश

संपादकीय

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है।

निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता है।

जान के लिए खतरा बन रहे हैं लिव-इन रिलेशनशिप

मनोज कुमार अग्रवाल

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस में शार्ट फिल्मों में काम दिलाने के बहाने सनी युवतियों को शिकार बनाता था। इसके बाद उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। पुलिस ने सनी के साथ उसकी मां रंजना और मां के प्रेमी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के मूल में लिवइन जिम्मेदार है।

आगरा के थाना खंदौली के यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को कंबल में लपेटकर फेंके गए महोबा की सोनाली के शव के मामले में पुलिस ने महिला के साथ लिव इन में रहने वाले प्रेमी सनी, उसकी मां रंजना और मां के प्रेमी प्रदीप को जेल भेजा है। मामले में मृतका की बहन भारती ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूछताछ में सामने आया है कि सनी शार्ट फिल्मों में काम दिलाने के बहाने युवतियों को जाल में फंसाकर देहव्यापार करवाता था। दूसरी युवती से दोस्ती का विरोध करने पर उसने सोनाली की हत्या कर दी थी।

दूसरा मामला मध्यप्रदेश में इंदौर के सुगनीदेवी कॉलेज परिसर में गंभीर हालत में मिली युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को राहगीरों ने घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल पहुंचाया था। उसके हाथों और शरीर पर कई टैटू बने हुए थे, वहीं शरीर पर ब्लेड से काटने के निशान भी पाए गए थे। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को उसके साथ ज्यादती की आशंका हुई, जिसके चलते सैंपल भी लिए गए थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती पर हमला उसके लिव-इन पार्टनर ने किया था। आरोपी ने हत्या की नीयत से पत्थर से वार किया था। देर रात इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।

लिव-इन रिलेशनशिप या सहमति संबंध एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री-पुरुष बिना विवाह किए पति-पत्नी की भांति रहने के साथ-साथ आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं व कई तो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं।

आपसी सहमति से कायम ऐसे संबंध पश्चिमी देशों में आम बात है। उनकी देखा-देखी भारत जैसे देशों में भी यह बुराई फैलने लगी है, जिसके दुखद परिणाम निकलने लगे हैं। लिव-इन रिलेशन में रहने वाले अपने पार्टनर की हत्या करने से भी संकोच नहीं करते पिछले दिनों में लगातार ऐसी वारदातों की झड़ी लगी हुई है।

आपको ऐसी कुछ और वारदातों से अवगत कराते हैं 27 नवम्बर, 2025 को दिल्ली के छावला इलाके में वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को जब उसकी लिव-इन पार्टनर ने शराब पीने से रोका तो वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

30 नवम्बर, 2025 को चेन्नई (तमिलनाडु) में अपने पति को छोड़ कर गोविंदराज नामक व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहने वाली प्रियंका नामक युवती ने किसी बात पर विवाद के चलते गोविंदराज को मार डाला।

8 दिसम्बर, 2025 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में रत्ना नामक विधवा ने अपनी 18 और 14 वर्षीय 2 बेटियों की सहायता से अपने लिव-इन प्रेमी सूर्य प्रताप सिंह की गला काट कर हत्या कर दी और पुलिस को बताया कि वह उसकी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था।

4 जनवरी, 2026 को ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दक्षिण कोरिया के एक नागरिक की चाकू से गोद कर हत्या कर देने के आरोप में उसकी मणिपुर निवासी लिव-इन पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर युवती से मारपीट करता था जिसका अंजाम इस दुखद घटना के रूप में निकला। 8 जनवरी, 2026 को झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रीति नामक महिला के साथ लिव-इन में रह रहे रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राम सिंह को प्रीति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।12 जनवरी, 2026 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आरती नामक महिला की हत्या के आरोप में उसके लिव-इन पार्टनर प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों में शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर प्रवीण कुमार ने आरती की पसलियों और छाती पर ताबड़तोड़ वार करके उसे मार डाला।18 जनवरी, 2026 को बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के चांदपुर मेंशीतल नामक एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर हरिओम सिंह की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान शीतल ने बताया कि रिलेशन के दौरान जब उसे गर्भ ठहरा तो हरिओम सिंह ने उसका गर्भपात करवा दिया और शादी के लिए बार-बार कहने पर भी वह मान नहीं रहा था। इस कारण वह नाराज होकर 15 जनवरी को अपने घर चली गई थी।घटना के दिन वह चांदपुर लौटी। दोनों ने पहले शराब पी। फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और शीतल ने शादी के लिए दोबारा दबाव बनाया तो हरिओम ने खुद को फांसी लगाने की धमकी देते हुए घर के बैड पर खड़े होकर अपने गले में फंदा डाल लिया।

"सड़क पर चलते हुए हम अक्सर यह मान लेते हैं कि नियम सिर्फ गाड़ियों के लिए होते हैं। पैदल चलना तो सबसे सरल काम है, इसमें भला नियम क्या होंगे? लेकिन यही सोच हर साल हजारों जिंदगियों की कीमत बन जाती है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में बड़ा हिस्सा पैदल यात्रियों का है। यह केवल तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाने का नतीजा नहीं, बल्कि पैदल चलने के गलत तरीकों का भी गंभीर परिणाम है। बचपन से हमें सिखाया गया कि ÷सड़क पर बाएं चलो÷, यह सीख इतनी गहरी बैठ गई कि हमने कभी उस पर सवाल ही नहीं उठाया। समय बदला, ट्रैफिक बढ़ा, सड़कें तेज हुईं, लेकिन हमारी आदतें वहीं की वहीं रहीं। अब वक्त आ गया है कि हम इस अधूरी सीख को पूरा करें और समझें कि पैदल यात्रियों के लिए सही दिशा कौन-सी है।"

पैदल चलने वालों के संवैधानिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम, सही दिशा में चलना अब विकल्प नहीं, ज़रूरत है

कांतिलाल मांडोत

जहां सड़क पर फुटपाथ नहीं है, वहां पैदल यात्रियों को दाई ओर चलना चाहिए। इसका कारण बेहद सीधा और जीवनरक्षक है। जब आप दाई ओर चलते हैं तो सामने से आने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं। खतरा आपकी आंखों के सामने होता है, पीठ पीछे नहीं। सामने से आती गाड़ी की गति, दूरी और ड्राइवर का व्यवहार देखकर आप समय रहते किनारे हो सकते हैं। इसके उलट जब आप बाई ओर चलते हैं तो वाहन पीछे से आते हैं। हॉर्न सुनाई न दे, मोबाइल पर ध्यान चला जाए या सड़क पर शोर हो, तो पीछे से आई तेज रफ्तार गाड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। दाई ओर चलने का नियम डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है।

दुनिया के कई देशों में यह बात सामान्य समझ का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब्रिटेन का हाईवे कोड और कई अंतरराष्ट्रीय रोड सेफ्टी गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि जहां फुटपाथ न हो, वहां हमेशा ट्रैफिक के विपरीत दिशा में चलना चाहिए। भारत में भी ट्रैफिक विशेषज्ञ, अदालतें और रोड सेफ्टी कमेटियां यही मानती हैं कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम यही है। इसके बावजूद आम लोगों में भ्रम बना हुआ है। शायद इसलिए क्योंकि हमने इसे कभी गंभीरता से अपनाया ही नहीं। हमें लगता है कि यह केवल कागजी नियम हैं, लेकिन जब हादसा होता है तब यही नियम जीवन और मृत्यु के बीच फर्क बन जाते हैं।

यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह कानूनी और आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है। अगर कोई पैदल यात्री गलत साइड चलते हुए दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे आंशिक रूप से अपनी लापरवाही का जिम्मेदार माना जा सकता है। कई मामलों में मुआवजा या बीमा क्लेम कम कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गलत दिशा में चलना न केवल जान जोखिम में डालता है, बल्कि दुर्घटना के बाद न्याय और आर्थिक सहायता की राह भी मुश्किल बना देता है। सड़क पर सही चलना अब सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

समस्या यह नहीं कि नियम मौजूद नहीं हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें आदत में नहीं ढाल पाए हैं। बचपन से जो सीख मिली, वही हमारी चाल में बस गई। सड़क पार करते समय तो हम दाएं-बाएं देखते हैं, लेकिन चलते समय सोचते ही नहीं कि किस तरफ चल रहे हैं। आदतें रातों-रात नहीं बदलतीं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, खुद को याद दिलाना पड़ता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लोग टोकेंगे भी, लेकिन हर सही आदत की शुरुआत थोड़ी असहज होती है। जब हेलमेट पहनना अनिवार्य हुआ था, तब भी लोगों को अटपटा लगा था। आज वही हेलमेट जान बचाने का सबसे बड़ा साधन है। दाई ओर चलने की आदत भी धीरे-धीरे उतनी ही स्वाभाविक हो सकती है।

इसके लिए सिर्फ सरकार या पुलिस को दोष देना आसान है, लेकिन समाधान हमारे हाथ में भी है। जब हम खुद सही चलेंगे, तभी बच्चे देखकर सीखेंगे। आज जो बच्चा अपने माता-पिता के साथ सड़क पर चलता है, वही कल का पैदल यात्री होगा। अगर वह हमें गलत साइड चलते देखेगा, तो वही सीखेगा। सड़क सुरक्षा का सबसे मजबूत पाठ स्कूलों और किताबों से पहले व्यवहार से आता है। घर से निकलते समय अगर हम खुद को यह याद दिला लें कि आज मुझे दाई ओर चलना है, तो यह छोटी-सी सोच बड़ी सुरक्षा बन सकती है।

शहरों में फुटपाथों की कमी एक सच्चाई है। हर जगह तुरंत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, यह संभव नहीं। ऐसे में पैदल यात्रियों के पास खुद को सुरक्षित रखने का सबसे सरल उपाय यही है कि वे सही दिशा में चलें। यह नियम किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है। अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक गाइडलाइंस और अदालतों के फैसले इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। संदेश साफ है कि जहां पैदल चलने की अलग व्यवस्था नहीं है, वहां दाई ओर चलना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नियम पता ही नहीं था। लेकिन जानकारी का अभाव अब बहाना नहीं रह गया है। अखबार, सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में यह मुद्दा सामने आ चुका है। अब सवाल यह नहीं कि नियम क्या है, सवाल यह है कि क्या हम उसे अपनाने को तैयार हैं। सड़क पर चलते हुए एक कदम दाई ओर ले जाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपनी पुरानी आदत को छोड़ना। लेकिन अगर इस बदलाव से किसी की जान बच सकती है, तो यह मेहनत बहुत छोटी है।

सड़कें साझा जगह हैं। वहां वाहन चालक, पैदल यात्री, साइकिल सवार सभी एक-दूसरे पर निर्भर हैं। सुरक्षा तभी संभव है जब हर कोई अपनी भूमिका समझे। वाहन चालकों को सतर्क रहना होगा, लेकिन पैदल यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सही दिशा में चलना उसी जिम्मेदारी का पहला कदम है। यह न तो डर का नियम है और न ही सजा का, यह जीवन का नियम है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि सही दिशा में चलना कोई बड़ा बलिदान नहीं मांगता। यह बस थोड़ी-सी जागरूकता, थोड़ी-सी प्रैक्टिस और थोड़े-से धैर्य की मांग करता है। अगर हम आज से यह तय कर लें कि जहां फुटपाथ नहीं है, वहां हम दाई ओर चलेंगे, तो शायद कल किसी परिवार को अपनों को खोने का दुख न झेलना पड़े। जान बचाने के लिए दिशा बदलनी पड़े, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की है, आइए सही दिशा में चलने की आदत डालें और सड़क को थोड़ा और सुरक्षित बनाएं।

भारत खूबसूरत मानवीय बोलियों, भाषाओं का एक विश्वप्रसिद्ध अभूतपूर्व संगम

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

भारत माता की गोद में एक से बढ़कर एक अनेक ऐसी खूबसूरत उपलब्धियां, हजारों वर्ष पूर्व से उपलब्ध है जिनकी अणखुट संरचना, प्राकृतिक खूबसूरती, विशाल भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों सहित अनेक अपार क्षमता वाली बौद्धिक संपदा का विशाल भंडार देख संपूर्ण विश्व हैरान था जिसपर नज़र लग गई थी जिससे हजारों वर्षो की गुलामी से आजादी के बाद 1947 में भारत का विभाजन हुआ। साथियों फ़िर भी हम अपनी मेहनत, लगन से फिर अपनी ताकत, ज़ाज़बे और जांबाज़ी के साथ वैश्विक पटल पर प्रमुख हस्ती के रूप में अपने हर क्षेत्र की समृद्धि व ताकत के आगाज़ के साथ वैश्विक पटल पर अहम स्थान रखते हैं, जिसे देखकर विश्व की नजरें फिर भारत की ओर आकस्मिकता से देश भारत का लोहा मान रही है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आज भारत उस स्थिति में है जहां भारत की ओर नज़र लगाने वाले को हज़ार बार सोचना पड़ेगा, यह है हमारा आज का भारत!

साथियों बात अगर हम अपनी संस्कृति, विशाल मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के साहित्यग्रंथों की करें तो यह हमारी पहचान है। यूं तो भारत में बावीस भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है परंतु पूरे भारत की बात करें तो यहां भाषाएं व उपभाषाएं हजारों की संख्या में होंगी, जिसकी रक्षा करना और विलुप्तता से बचाने की ज़वाबदारी हमारे आज के युवाओं के ऊपर है क्योंकि आज हमारे देश की 68 प्रतिशत आबादी युवा है और इस युवा भारत के युवाओं को ही हमारी संस्कृति, भाषाओं को जीवित रखना है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को महत्व देना होगा और अपने समाज, घर, क्षेत्र में अपनी मातृभाषा में बात करना होगा ताकि उसे हम विलुप्तता से बचा सके, आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचलन कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर के युवाओं में इसका क्रेज अधिक महसूस किया जा रहा है जो बड़े शहरों से होकर अब हमारे छोटे शहरों गांवों में भी फैलने की संभावना बढ़ गई है। जिसका संज्ञान बुजुर्गो को लेना होगा और युवाओं को अपनी मातृभाषा में बोलने, संस्कृति, साहित्यग्रंथों, भाषाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराकर उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा ताकि भारतीय धरोहर को विलुप्तता से बचाया जा सके। हमने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई बार देखा, पड़ा, वह सुना है कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति का संज्ञान इस भाषाई क्षेत्र की ओर बहुत अधिक है,और हर मौके पर इस दिशा में सुझाव, मार्गदर्शन, अपील, प्रोत्साहन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जो काबिले तारीफ है।

साथियों बात अगर हम माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा एक विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस समारोह को संबोधन करने की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने इस संबंध में

विश्वोविद्यालयों से भारतीय भाषाओं में उन्नत अनुसंधान करने तथा भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में सुधार लाने का सुझाव लाने की अपील की, जिससे कि उनकी व्याभपक पहुंच तथा शिक्षा क्षेत्र में उपयोग को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने ने आज विभिन्नत भारतीय भाषाओं में साहित्यिक ग्रंथों के अनुवादों की संख्याक बढ़ाने के लिए सक्रिय तथा ठोस प्रयासों की अपील की। इस संबंध में उन्होंरने क्षेत्रीय भारतीय साहित्यं की समृद्ध धरोहर को लोगों की मातृभाषाओं में सुलभ कराने के लिए अनुवाद में प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ उठाने का सुझाव दिया। यह देखते हुए कि भूमंडलीकरण का व्या पक प्रभाव है, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवा अपनी सांस्कृोतिक विरासत से संपर्क बनाए रखे। पहचान बनाने तथा युवाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में भाषा के महत्व को देखते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व का अनुभव करना चाहिए। बाद में, उन्होंने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत की चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आगन्तुक पुस्तिका में लिखने के दौरान उन्होंने तेलंगाना और हरियाणा के जोड़ीदार राज्यों की संस्कृति को प्रदर्शित करने में आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। लोगों को प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रोत्सा हित करते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसी पहलें जोड़ीदार राज्यों की समृद्ध सांस्कृयतिक विरासत को प्रचारित करने तथा लोगों के बीच आपसी संपर्कों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्यि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना तथा बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्सा हित करना है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य रूप से उच्च तर शिक्षा तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से संपर्क बनाए रखना अत्यंत ज़रूरी है उनको अपनी मातृभाषा में बोलने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए तथा भारत खूबसूरत मानवीय बोलियों, भाषाओं का विश्वप्रसिद्ध संगम है जिसे संजोकर रखने का हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।

(संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी)

डिजिटल क्रांति पर साइबर प्रहार गंभीर चुनौती

डिजिटल युग ने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं ने लेन-देन को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया है। आज एक सामान्य नागरिक भी कुछ सेकंड में देश के किसी भी कोने में धन भेज सकता है, बिल जमा कर सकता है या निवेश कर सकता है। यही डिजिटल क्रांति 'नए भारत' और 'विकसित भारत' की आधारशिला मानी जा रही है। किंतु इसी क्रांति के साथ एक गहरी विडंबना भी उभरकर सामने आई है-डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर लूट की भयावह बढ़ोतरी। हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की घटनाएँ न केवल आमजन को आर्थिक रूप से आहत कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा रही हैं।

ललित गर्ग

डिजिटल व्यवस्था की मूल आत्मा 'विश्वास' है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन पर उभरे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो वह केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उस संपूर्ण तंत्र पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित लेन-देन का आश्वासन देता है। किंतु जब यही विश्वास ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, निवेश घोटालों और पहचान चोरी के कारण टूटने लगता है, तब डिजिटल विकास की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में नकली नोटों की भरमार हो जाए तो मुद्रा पर विश्वास डगमगा जाता है, उसी प्रकार यदि डिजिटल लेन-देन में ठगी सामान्य अनुभव बन जाए, तो नागरिक डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाने लगते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत हानि का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के लिए भी खतरे की घंटी है। परंपरागत अपराधों और डिजिटल अपराधों की तुलना करें तो दोनों के स्वरूप और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। पहले चोरी या डकैती किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती थी, अपराधी की पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट होती थी और जांच प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी। डिजिटल अपराधों में अपराधी अदृश्य है, वह किसी दूसरे राज्य या देश में बैठकर वारदात कर सकता है, और कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों को निशाना बना सकता है। पारंपरिक अपराध में जोखिम अपराधी के लिए अधिक था, डिजिटल अपराध में जोखिम कम और लाभ अधिक है। यही असंतुलन इसे अत्यंत खतरनाक बनाता है। एक अन्य तुलनात्मक पक्ष यह है कि डिजिटल अपराधों में पीड़ित की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी अलग होती है। ठगी का शिकार व्यक्ति स्वयं को अपराधी के सामने असहाय पाता है। पुलिस और साइबर क्राइम कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे तकनीकी कारणों का हवाला देकर लौटा दिया जाता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास जन्म लेता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल है, समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, और समय पर कार्रवाई न होने से धन की रिकवरी असंभव हो जाती है। इससे यह धारणा बनती है कि डिजिटल अपराध का कोई वास्तविक दंड नहीं है। सरकार और न्यायपालिका ने समय-समय पर इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है। शीर्ष अदालत द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखना इस बात का संकेत है कि यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक आक्रमण भी हो सकता है। किंतु नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। अनेक प्लेटफार्म और हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी स्पष्ट दिखती है। यदि शिकायत के बाद प्रारंभिक ÷गोल्डन ऑवर÷ में ही बैंक खाते फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रैक करने की प्रभावी व्यवस्था न हो, तो बाद की प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह जाती है।

वित्तीय प्रणाली की दृष्टि से देखें तो डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना निवेश, उपभोग और बैंकिंग व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आमजन को यह आशंका सताने लगे कि ऑनलाइन निवेश योजनाएँ या भुगतान सुरक्षित नहीं हैं, तो वह नकद लेन-देन की ओर लौट सकता है। यह प्रवृत्ति सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की नीति को कमजोर करेगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों के लिए भी यह संकेत नकारात्मक हो सकता है कि साइबर सुरक्षा का ढांचा पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है। अतः यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का भी केंद्रीय प्रश्न है। समाधान के स्तर पर तुलनात्मक रूप से देखें तो विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखा है। वहाँ विशेषीकृत एजेंसियाँ, उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ, त्वरित डेटा साझा करने की प्रणाली और सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं। भारत में भी साइबर क्राइम ब्यूरो और डिजिटल सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, परंतु उनकी क्षमता, संसाधन और प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस बल को केवल पारंपरिक अपराधों की नहीं, बल्कि डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण की भी विशेषज्ञता दी जानी चाहिए। जब तक जांच एजेंसियाँ तकनीकी रूप से अपराधियों से एक कदम आगे नहीं होंगी, तब तक रोकथाम कठिन रहेगी।

एक महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक जागरूकता का भी है। तकनीक जितनी उन्नत होती है, अपराधी भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। अतः केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि लोग संदिग्ध लिंक, कॉल और निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि जागरूकता का दायित्व पीड़ित पर डालकर व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सुरक्षा का मूल दायित्व तंत्र का है, नागरिक का नहीं। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी इस समस्या को जटिल बनाते हैं। यदि बैंक या भुगतान प्लेटफार्म समय पर कार्रवाई नहीं करते, या आंतरिक मिलीभगत से फर्जी खाते संचालित होते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली, जवाबदेही और कठोर दंड अनिवार्य हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों की केवाईसी प्रक्रिया को अधिक कठोर और वास्तविक बनाना होगा, ताकि फर्जी पहचान के माध्यम से खाते खोलना कठिन हो।

अंततः डिजिटल क्रांति का उद्देश्य सुविधा, पारदर्शिता और समृद्धि है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसका नैतिक औचित्य कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, और न ही यह वांछनीय है। किंतु इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना अनिवार्य है। सरकार को नीति, तकनीक और प्रशासन-तीनों स्तरों पर समन्वित रणनीति अपनानी होगी। साइबर अपराध के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को समयबद्ध राहत, जांच एजेंसियों का सशक्तीकरण और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही-ये सब मिलकर ही धोखाधड़ी मुक्त डिजिटल परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। डिजिटल भारत की सफलता केवल ऐप्स और आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस विश्वास से मापी जाएगी जो नागरिक अपने मोबाइल स्क्रीन पर उभरते हर ट्रांजैक्शन संदेश के साथ महसूस करता है। यदि यह विश्वास सुरक्षित रहा, तो डिजिटल क्रांति राष्ट्र को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगीय यदि यह टूट गया, तो समृद्धि का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अतः समय की मांग है कि डिजिटल धोखाधड़ी को एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर उसके समाधान की दिशा में ठोस, निर्णायक और पारदर्शी कदम उठाए जाएँ, ताकि विकसित भारत की आधारशिला मजबूत और अडिग रह सके।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के दिए सख्त निर्देश

समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन से ही मिलेगी जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा : कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डी. राहुल वेंकट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे की अध्यक्षता में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अस्पताल अधीक्षक, समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जिला नोडल अधिकारी एवं सहायक जिला नोडल अधिकारी, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संस्था प्रभारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों एवं सेक्टर चिकित्सा अधिकारियों को आधार बेस्ड अटेंडेंस प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियत समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में समय पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन की सतत एवं नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका सूचीबद्ध पंजीयन, 24×7 निगरानी, वैकल्पिक रूप से एएनसी व्यवस्था, आवश्यकतानुसार एफआरयू (स्न्क्र) का चिन्हांकन तथा समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (ष्ट।ह्र) को ऑनलाइन एंट्री का कार्य नियमित रूप से करने के लिए कहा गया। इस संबंध में किसी भी कर्मचारी द्वारा शासकीय कार्य के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई।

टीकाकरण, टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए पृथक कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में शत-प्रतिशत वय वंदन एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए।

जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (ह्न्क्र्स) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सक्षम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक के दौरान 29 एवं 30 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक रणनीति बनाकर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश 11 फरवरी 2026 को दिए गए। अंत में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने निर्देशित किया कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं का पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए आम नागरिकों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नपा में भ्रष्टाचार मामला, अध्यक्ष गायत्री शर्मा और सीएमओ 24 फरवरी को भोपाल तलब

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश ने शिवपुरी नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने अध्यक्ष गायत्री शर्मा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 24 फरवरी 2026 को भोपाल तलब किया है। मंत्रालय के नवीन वल्लभ भवन में सचिव के समक्ष दोपहर 12 बजे सुनवाई निर्धारित की गई है। विभाग ने लगभग एक माह पहले अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अध्यक्ष ने करीब 150 पेज का विस्तृत जवाब भेजा था, जिसमें नगर पालिका के रिकॉर्ड भी संलग्न थे। हालांकि, विभाग इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया है।

विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख के साथ नियत तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व में हुई प्रशासनिक जांच में अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाए गए थे। कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को सही मानते हुए भोपाल स्थित विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसी अनुशंसा के बाद यह प्रकरण मंत्रालय तक पहुंचा और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई 24 फरवरी को मंत्रालय के नवीन वल्लभ भवन क्रमांक-02, द्वितीय तल, ए-विंग, कक्ष क्रमांक ए-203 में मध्यप्रदेश शासन के सचिव के समक्ष होगी। इस संबंध में जारी पत्र पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. तोषण कुमार बडिये के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित हैं। अब सभी की निगाहें 24 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं। इस पेशी के बाद यह तय होगा कि शिवपुरी नगर पालिका परिषद के इस बहुचर्चित मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या कोई बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है।

प्रशासन की सतर्कता

जगन्नाथ मंदिर 16 को शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी नियुक्त

एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए 16 फरवरी 2026 को जगन्नाथ मंदिर, चिरमिरी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में विभिन्न प्रमुख स्थलों पर अधिकारियों को कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के अनुसार हवन एवं पूजा स्थल तथा मुख्य मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के लिए विजयेन्द्र सारथी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खड़गवां/चिरमिरी को दायित्व सौंपा गया है। उनके सहयोग हेतु विनीत कुमार सिंह, नजूल तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ एवं श्रुति धुर्वे, तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं मुख्य मंच, कार्यक्रम स्थल, पत्थर शिलालेख एवं हेलीपैड क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लिंगराज सिदार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ को जिम्मेदारी दी गई है। उनके सहयोग के लिए समीर शर्मा, तहसीलदार चिरमिरी तथा नीरज कांत तिवारी, तहसीलदार भरतपुर को सहायक अधिकारी बनाया गया है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम दिवस पर निर्धारित स्थलों में उपस्थित रहकर समन्वय, सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

शिवपुरी के प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी, यशोधरा राजे सिंधिया ने कराया था जीर्णोद्धार

मूर्ति, दान के पैसे, माइक और यूजिक सिस्टम भी ले गए

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन नवग्रह हनुमान मंदिर में बुधवार रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अष्टधातु की राधा-कृष्ण मूर्ति, दान पेटी की नगदी सहित मंदिर में रखे हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर के महंत मनीष शर्मा ने बताया कि सुबह मंगल आरती के लिए पहुंचे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। अंदर दान पेटी का ताला भी टूटा था और उसमें रखी दान के पैसे भी गायब थे।

म्यूजिक सिस्टम और पूजा सामग्री भी ले गए चोर: महंत के मुताबिक, चोर अष्टधातु की मूर्ति के अलावा करीब 16 हजार रुपए का नया म्यूजिक सिस्टम, पांच माइक, झालर और अन्य पूजा सामग्री भी ले गए। सूचना मिलते ही फिजिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सुरक्षा व्यवस्था पर महंत ने उठाए सवाल: महंत मनीष शर्मा ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार पूर्व मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने धर्मस्व विभाग से जुड़वाकर कराया था। इसके बाद भी मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। मंदिर में न बाउंड्री वॉल बनी और न ही पुजारी के रहने की व्यवस्था की गई। उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण चोर आसानी से मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे पाए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की: थाना प्रभारी नम्रता भदोरिया ने बताया कि मौके का मुआयना किया गया है। छोटी अष्टधातु की मूर्ति, दो से तीन हजार रुपए नगदी और कुछ सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अमृतधारा महोत्सव 2026 के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। अमृतधारा महोत्सव 2026 का आयोजन 15 फरवरी 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का आगमन संभावित है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने अमृतधारा महोत्सव की आवश्यक तैयारियों के संबंध में अपर कलेक्टर नम्रता आंनद डोंगरे को नोडल अधिकारी एवं लिंगराज सिदार संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपें गये हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा को विभागों को स्टॉल आबंटन एवं हितग्राहियों को सामग्री, चेक, उपकरण आदि का वितरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था, रूट चार्ट, पार्किंग, वाहन व्यवस्था, टैअफिक, ब्लड ग्रुप व्यवस्था, मुख्य मंच एवं कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केल्हारी, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, उप संचालक उद्यानिकी एवं जिला नोडल अधिकारी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को मुख्य मंच व्यवस्था, बैनर, फ्लैक्स, पुष्प सज्जा, बैठक व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार, नियत स्थल पर हैलीपैड, मंच एवं वीआईपी तथा कलाकार हेतु ग्रीन रूम का निर्माण, वेटिंग रूम, बैरीकेटिंग, टेंट आदि का सम्पूर्ण व्यवस्था, मंच के समीप पृथक से हितग्राहियों के स्टॉल से मुख्य मंच तक आने हेतु सीढी, रैम्प का आवश्यकतानुसार निर्माण तथा समस्त कार्यक्रम स्थल पर आवश्यकतानुसार समतलीकरण की जिम्मेदारी सौपी गई है।

इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी वन, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ को सम्पूर्ण कार्यक्रम एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बांस-बल्ली एवं फारेस्ट रेस्ट हाउस में अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं। कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी), कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ एवं ई-डिस्ट्रिक मैनेजर को कार्यक्रम स्थल पर माईक, साउड सिस्टम मंच एवं आस-पास लाईट, पीए सिस्टम की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन लगवाना, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर सहित, मंच व दर्शक दीर्घा में प्रकाश की व्यवस्था, कार्यक्रम पर एक दिवस पूर्व साउड सिस्टम एवं एलईडी स्क्रीन की जांच पड़ताल कर ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ को आमंत्रण पत्र प्रिंट करना, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनेन्द्रगढ़ एवं जिला परिवहन अधिकारी को प्रोटोकॉल एवं कलाकार हेतु परिवहन व्यवस्था, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केल्हारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी एवं उद्घोषक व्यवस्था, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को कार्यक्रम के दौरान मंच पर दीप प्रज्जवलन कार्यक्रम का संपूर्ण प्रभार, मंच संचालन एवं स्थानीय कलाकारों को लाने, ले जाने, ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मनेन्द्रगढ, नगर पंचायत खोंगापानी, नई लेदरी, झारराखांड एवं जनकपुर को संस्कृति विभाग से आये कलाकारों की आवश्यक व्यवस्था, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का एल्बम तैयार कराकर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जनकपुर में आबादी वाले इलाके में घूम रहा भालू पकड़ाया, ग्रामीणों को मिली राहत

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के जनकपुर नगर पंचायत क्षेत्र में कई दिनों से भालू घूम रहा था। वह बार-बार आबादी वाले इलाके में आ रहा था, जिससे लोगों में डर का माहौल था। स्थिति को गंभीर देखते हुए वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। बुधवार बीती रात विशेष अभियान चलाकर भालू को सुरक्षित पकड़ लिया गया। वनमंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ के निर्देश पर प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक एवं प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास निकुंज के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया। यह कार्रवाई देर रात सतर्कता और कुशल समन्वय के साथ की गई। वन अमले ने एक नर भालू को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद किया।

भालू को प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया: इसके बाद विधिवत पंचनामा तैयार किया गया। भालू को वन विभाग की गाड़ी से गांव से काफी दूर सुरक्षित वन क्षेत्र में ले जाकर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। पिंजड़े से मुक्त होते ही भालू तेजी से जंगल की ओर भाग गया। इस सफल कार्रवाई के बाद जनकपुर क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। प्रभारी रेंजर ने बताया कि रेस्क्यू अभियान में बीएफओ पतवाही राजेंद्र परस्ते, परिक्षेत्र सहायक मसौरा प्रदीप दुबे, वनरक्षक गजाधर सिंह सहित वन अमले की सक्रिय भूमिका रही।

6 दिन से जल सप्लाई ठप, जियो की खुदाई में फूटी थी लाइन; लोग काम छोड़कर भर रहे पानी

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शहर में पिछले 6 दिनों से गंभीर जल संकट बना हुआ है। मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। लोग अपने दैनिक काम-धंधे छोड़कर पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। हालांकि, नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड़ ने दावा किया है कि अब खराबी ठीक कर ली गई है और आज (गुरुवार) से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। यह संकट 6 फरवरी को जियो मोबाइल कंपनी द्वारा केबल लाइन बिछाने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान खड़ा हुआ। मड़ीखेड़ा बांध के पास मुख्य पाइपलाइन टूट गई थी। कंपनी ने अपने खर्च पर पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव दिया था। नगर पालिका ने दावा किया था कि 2 दिन में (8 फरवरी तक) सप्लाई बहाल हो जाएगी, लेकिन 12 फरवरी तक भी नलों में पानी नहीं आया। शहर में अभी टैंकरों से काम चलाया जा रहा है।

मजदूरी छोड़ पानी भरने को मजबूर: पानी की किल्लत के चलते फिजिकल क्षेत्र स्थित पीएचई कार्यालय के पास सरकारी बोरवेल पर सुबह से देर रात तक लंबी कतारें लगी हैं। लोग कार, बाइक, स्कूटी और हाथ ठेला से पानी ढो रहे हैं। आकाश शाक्य ने बताया कि वे पिछले 8 दिनों से मजदूरी पर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि पानी भरना उनकी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी संचालक शुभम राठौर को काली माता मंदिर क्षेत्र से पानी लाना पड़ रहा है। फॉरेस्ट कर्मचारी जय नारायण श्रीवास्तव भी 3 दिन से ड्यूटी छोड़कर पानी भर रहे हैं। वार्ड 19 निवासी मनोज खटीक ने बताया कि उनके क्षेत्र में सप्लाई पूरी तरह बंद है।

हॉस्टल से 3 छात्र लापता, सुरक्षा पर सवाल; तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी के नौहरी चक स्थित राजपूत हॉस्टल से तीन छात्र लापता हो गए हैं। हॉस्टल ईस्टर्न हाईट स्कूल के पास है। घटना के बाद परिजनों ने चिंता व्यक्त की है, और हॉस्टल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। हॉस्टल संचालक राम सिंह राजपूत ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी की शाम करीब 5 बजे जब वे हॉस्टल में छात्रों की उपस्थिति जांच रहे थे, तब तीन छात्र अपने कमरों में नहीं मिले। अन्य छात्रों से पूछताछ करने पर पता चला कि तीनों लड़के शाम 4:30 बजे के आसपास बिना किसी को बताए हॉस्टल से बाहर चले गए थे।

लापता छात्रों की पहचान प्रशांत धाकड़ (15 वर्ष, कक्षा 8, निवासी नमोनगर कॉलोनी शिवपुरी), दीपांश लोधी (17 वर्ष, कक्षा 10, निवासी समोहा, थाना करैरा) और आसेन्द्र लोधी (14 वर्ष, कक्षा 10, निवासी ग्राम दुल्हई, थाना भौती, जिला शिवपुरी) के रूप में हुई है। छात्रों के काफी देर तक वापस न लौटने पर हॉस्टल प्रबंधन ने उनके परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने भी पुष्टि की कि बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं।

हॉस्टल और परिवार के लोगों ने खोजे, नहीं मिले: हॉस्टल प्रबंधन और परिजनों ने मिलकर बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और छात्रों के परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। फरियादी राम सिंह राजपूत ने आशंका व्यक्त की है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तीनों छात्रों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया हो सकता है। इस मामले में हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है। बताया गया है कि हॉस्टल परिसर में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और बाहर लगा एक कैमरा भी खराब पड़ा था। प्रवेश और निकास द्वार पर सख्त निगरानी व्यवस्था न होने के कारण तीनों छात्र बिना किसी को बताए बाहर निकल गए। अभिभावकों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रशांत धाकड़ पूर्व में एक अन्य हॉस्टल में रह चुका है। 28 मई 2025 को वह वहां से भी तीन अन्य छात्रों के साथ भाग गया था, जिसके बाद उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। बाद में परिजनों ने उसका दाखिला राजपूत हॉस्टल में कराया था। पुलिस इस पुराने घटनाक्रम को भी जांच में शामिल कर रही है। कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आसपास के थानों में सूचना भेज दी है। संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

बिजली विकास का जिलानामा, बिजली उपभोक्ता 6 गुना, सिंचाई पंप 9 गुना बढ़े

25 वर्षों में बिजली नेटवर्क का बड़ा विस्तार, कृषि और उद्योग को मिली नई ऊर्जा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत अंबिकापुर क्षेत्र में आने वाले एमसीबी जिले में पिछले 25 वर्षों के दौरान विद्युत अधोसंरचना एवं उपभोक्ता सेवाओं में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया है। वर्ष 2000 में अविभाजित कोरिया जिले का हिस्सा रहे इस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 6228 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2022 में अलग जिला बनने के बाद 4227 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसके बावजूद विद्युत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया गया है।

आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 21,209 से बढ़कर 57,549 हो गई है, जो लगभग 200 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। उच्च दाब उपभोक्ता 15 से बढ़कर 37 तथा निम्न दाब उपभोक्ता 9,505 से बढ़कर 57,549 तक पहुंच गए हैं। बीपीएल कनेक्शन 3,562 से बढ़कर 22,679 और घरेलू उपभोक्ता 7,999 से बढ़कर 27,213 हो गए हैं। वहीं सिंचाई पंप उपभोक्ताओं की संख्या 128 से बढ़कर 1,159 तक पहुंच गई है, जो कृषि क्षेत्र में विद्युत सुविधाओं के व्यापक विस्तार का संकेत है। विद्युत अधोसंरचना में भी व्यापक वृद्धि हुई है। जिले में 132/33 केवी उपकेंद्रों की संख्या 1 से बढ़कर 2 (चैनपुर एवं बहरासी) हो गई है, जबकि 33/11 केवी उपकेंद्र 4 से बढ़कर 13 हो गए हैं। पावर ट्रांसफार्मर 5 से बढ़कर 17 तथा वितरण ट्रांसफार्मर 276 से बढ़कर 3,018 तक पहुंच गए हैं। उच्च दाब लाइनों की लंबाई 734 किमी से बढ़कर 3,718 किमी और निम्न दाब लाइनों की लंबाई 368 किमी से बढ़कर 3,429 किमी हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा एक जोन एवं 8 वितरण केंद्रों के माध्यम से जिले के सभी गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया गया है तथा 57 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। विद्युत सेवाओं के विस्तार से कृषि, उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिला है और जिले के समग्र विकास को नई गति मिली है।

रतलाम में तीन जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का रहेगा स्टॉपेज

बांद्रा टर्मिनस से वीरांगना लक्ष्मीबाई, सूबेदारगंज व असारवा-आगरा कैंट के बीच चलेगी

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं होली त्योहार को देखते हुए तीन जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बांद्रा टर्मिनस- सूबेदारगंज तथा असारवा-आगरा कैंट के बीच स्पेशल किराये के साथ चलेगी। इन ट्रेनों की शुरूआत मार्च माह के पहले सप्ताह से होगी।

बांद्रा टर्मिनस-लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट : ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 5.10 बजे चलेगी। यह ट्रेन 07 मार्च से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी। रतलाम मंडल के दाहोद (12.43/12.45), रतलाम (14.30/14.40), नागदा (15.43/15.45), उज्जैन (16.55/17.10)एवं मक्सी (18.00/18.02), होते हुए अगले दिन 5 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 16.50 बजे प्रस्थान करेगी। रतलाम मंडल के मक्सी (03.05/03.07), उज्जैन (03.50/04.00), नागदा (05.08/05.10), रतलाम (06.05/06.15), एवं दाहोद (07.39/07.41), होते हुए अगले दिन 16.10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 मार्च से 26 मार्च 26 तक चलेगी।

इन स्टेशनों पर रहेगा स्टॉपेज : यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, उधना, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, ब्यावरा राजगढ़, चाचुरा बिनागंज, रूठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा एवं दतिया स्टेशनों पर स्टॉपेज रहेगा। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट विकली स्पेशल : ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 11.15 बजे चलेगी। रतलाम (21.25/21.30), होते हुए अगले दिन 17 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 मार्च से 31 मार्च 26 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04125 सूबेदारगंज-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक सोमवार को सूबेदारगंज से 5.20 बजे चलेगी। रतलाम (21.45/21.55), होते हुए अगले दिन 9.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 मार्च से 30 मार्च 26 तक चलेगी।

यहां रहेगा स्टॉपेज : यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3 टियर, एसी 3 टियर (इकोनॉमी), स्लीप क्लास एवं जनरल सेकंड कोच होंगे।

असारवा-आगरा कैंट स्पेशल (सप्ताह में 5 दिन) : ट्रेन संख्या 01920 असारवा-आगरा कैंट स्पेशल मंगलवार एवं बुधवार को छोड़कर प्रतिदिन असारवा से 14.50 बजे चलेगी।

खरगोन में ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, निजीकरण विनिवेश नीतियों के खिलाफ नारेबाजी

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन में गुरुवार को ट्रेड यूनियनों ने निजीकरण, विनिवेश और श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि, इस बंद का शहर के बाजार पर कोई खास असर नहीं दिखा और दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहीं।

दोपहर में राधावल्लभ मार्केट में विभिन्न यूनियन के कर्मचारियों ने छुट्टी लेकर हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने बीमा क्षेत्र में लागू की जा रही निजीकरण, विनिवेश और श्रम विरोधी नीतियों का विरोध किया। इस दौरान, प्रतिनिधियों ने एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में विनिवेश की नीति को तत्काल बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की अनुमति से सार्वजनिक बीमा संस्थानों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।

उन्होंने स्थायी नियुक्तियों पर रोक और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग को सेवाओं की गुणवत्ता और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया।

स्टाफ की कमी के बावजूद नई भर्ती न होने से कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ रहा है। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन खरगोन के सचिव और वर्किंग कमेटी मेंबर आशीष पगारे ने इस दौरान अमेरिका के साथ ट्रेड डील को किसानों के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसानों को सालाना 65 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। पगारे ने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी बीमा योजनाओं को कमजोर करने के प्रयासों को रोकने की भी मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम कानूनों में किए जा रहे कर्मचारी विरोधी संशोधनों को वापस लिया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि बीमा क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। इन्हें कमजोर करना न केवल कर्मचारियों बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों और आम जनता के हितों पर सीधा हमला होगा।

ट्रॉली पलटी, 23 घायल में से 6 नर्मदापुरम रेफर

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में लगभग 23 लोग घायल हो गए। घटना सलकनपुर के पास नकटीतलाई वेयर हाउस के निकट हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्राली पलट गई। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में घायल हुए 23 लोगों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद नर्मदापुरम रेफर किया गया है। अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी में भर्ती कराया गया है।

9 साल के बच्चे के जबड़े का सफल ऑपरेशन

सागर में 3 साल से मुंह बंद था, लिक्विड डाइट पर था जिंदा

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (ब्रस्ट) में डॉक्टरों की टीम ने एक 9 वर्षीय बालक के जबड़े का जटिल और सफल ऑपरेशन किया है। यह बच्चा पिछले तीन सालों से अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था और केवल लिक्विड डाइट (तरल आहार) पर निर्भर था। डेंटल और एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने सर्जरी कर उसे टेम्पोरोमैंडिबुलर ,जॉइंट एंकिलोसिसढ (TMJ Ankylosis) जैसी गंभीर स्थिति से निजात दिलाई है। ऑपरेशन के तुरंत बाद बच्चा 30 मिमी से अधिक मुंह खोलने में सक्षम हो गया है। परिजन ने बालक को बीएमसी में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि 9 वर्षीय बालक का 3 साल से मुंह बंद था। वह खाना नहीं खा पाता था। थ्री डीसीटी (3D CT) स्कैन में जबड़े की हड्डियों का आपस में जुड़ना (ऋस्ब्ध एंकायलोसिस) पाया गया, जिसके बाद ऑपरेशन का निर्णय लिया गया।

बेहोश करना था चुनौती, विशेष तकनीक अपनाई : बच्चे का मुंह पूरी तरह बंद होने के कारण उसे सामान्य तरीके से बेहोश करना असंभव था। डॉ. शशि वाला के नेतृत्व में एनेस्थीसिया टीम ने नेजल फाइबर-ऑप्टिक इंट्यूबेशन (Nasal Fiber-Optic Intubation) जैसी विशेष तकनीक का उपयोग कर इस बाधा को पार किया। ऑपरेशन के बाद डॉ. सर्वेश जैन की देखरेख में बच्चे को आईसीयू में रखा गया, जहां से अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलटा, 12 घायल, फसल काटने दमोह जा रहे थे

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर में मजदूरों से भरा एक ओवरलोड पिकअप वाहन पलट गया। बुधवार दोपहर हुए हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन में 30 से अधिक मजदूर सवार थे। ये सभी छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र से दमोह जिले में फसल कटाई के लिए जा रहे थे। रास्ते में यह वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत वाले घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल बालाप्रसाद ने बताया कि घटना किशनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगदा रोड उचेहरा के पास की है। वे अपने गांव टिपारी से दमोह जिले के निवार जा रहे थे। गाड़ी में 30 से ज्यादा मजदूर सवार थे। रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोककर आलू खरीदे और उन्हें गाड़ी में रख लिया। इसके बाद जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वह अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायल इमरत ने भी घटना की पुष्टि की है। प्रत्यक्षदर्शी जगदीश चौबे का कहना है कि ड्राइवर जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठाए हुए था और उसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग और असावधानी दुर्घटना की मुख्य वजह रही। डायल 112 में तैनात आरक्षक राधे शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से 6 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

विधिक दक्षता सुदृढ़ करने दो दिवसीय सेमिनार संपन्न

एससी/एसटी एक्ट व सूचना का अधिकार अधिनियम पर अधिकारियों को मिला विशेष प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी भोपाल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम विषयों पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सेमिनार का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों की विधिक समझ को सुदृढ़ करना और संवेदनशील मामलों में विधि अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा।

प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से आए अधिकारियों ने प्रशिक्षण में सहभागिता की। विशेषज्ञों द्वारा अधिनियमों के नवीनतम संशोधनों, महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याओं तथा प्रासंगिक प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में त्वरित एवं निष्पक्ष जांच, पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

केस स्टडी और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से अधिकारियों को जटिल प्रकरणों के समाधान की रणनीतियां समझाई गईं। प्रशिक्षण के दौरान संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। समापन अवसर पर पुलिस अकादमी के उपनिदेशक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए कहा कि विधिक दक्षता ही प्रभावी एवं जवाबदेह पुलिसिंग की आधारशिला है।

पंचायत ने ढाई लाख के टैंकर 25 हजार में बेचे, ग्रामीणों ने शिकायत की तो एक वापस आया

सचिव और सरपंच पर गड़बड़ी का आरोप

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। जनपद पंचायत पुनासा की ग्राम पंचायत दूधवास में पदस्थ सचिव और सरपंच पति पर सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर मामले में जिला स्तरीय जांच दल गठित करने व जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बताते है कि दोनों टैंकर पूर्व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान और पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा ने गांव में जलसंकट को देखते हुए प्रदान किए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि, 20 जनवरी को पंचायत सचिव अमजद खान और सरपंच पति योगेश यादव ने आपसी साठगांठ कर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश, पूर्वानुमति या नीलामी किए बिना दो पेयजल टैंकर कबाड़ियों को बेच दिए।

दोनों टैंकर अच्छी स्थिति में थे और नए टैंकर की कीमत करीब ढाई लाख रुपए प्रति टैंकर है, लेकिन उन्हें मात्र 25-25 हजार रुपए में स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया। यह राशि पंचायत के कोषालय में भी जमा नहीं की गई।

मामला उठाया तो थाने में झूठी शिकायत कर दी : ग्रामीण दीपक राठौड़ ने बताया कि, टैंकर बिक्री से प्राप्त राशि न तो शासकीय कोषालय में जमा की गई और न ही पंचायत के खाते में दर्शाई गई। आरोप है कि राशि का दुरुपयोग किया गया है। जब कुछ ग्रामीणों ने नियमों का हवाला दिया तो सरपंच पति द्वारा उनके खिलाफ मूंदी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

सिवनी में पानी के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीणनेशनल हाइवे पर किया चक्काजाम

मीडिया ऑडीटर, सिवनी (निप्र)। सिवनी जिले के गणेशगंज क्षेत्र स्थित ग्राम बिजना में पेयजल संकट है। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चक्काजाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण गणेशगंज और बिजना के बीच मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

सूखे हैंडपंप और दूर-दराज से पानी लाना बना मजबूरी : ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश हैंडपंप और पारंपरिक जलस्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। पीने के पानी के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मीलों पैदल चलकर दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कामों के लिए भी बूंद-बूंद पानी जुटाना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या से आक्रोशित होकर 100 से अधिक ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई शुरू की जाए।

प्रशासनिक आश्वासनों से नाराजगी : चक्काजाम कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे इस समस्या को लेकर कई बार जनसुनवाई में गुहार लगा चुके हैं। पूर्व में कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गांव का दौरा कर जल्द समाधान का वादा भी किया था, लेकिन हकीकत में अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार मिल रहे आश्वासनों के कारण ही उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अधिकारियों की समझाइश पर खुला मार्ग : हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। अपर कलेक्टर सी.एल. चिनाप ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया और आवागमन बहाल हो सका।

रायसेन में वाहन की टक्कर से घायल तेंदुए की तलाश

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन के भोपाल-विदिशा बायपास पर मंगलवार रात वाहन की टक्कर से घायल हुए तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग ने बड़ा सर्च अभियान शुरू कर दिया है। रातापानी अभ्यारण्य की डॉग एस्कॉर्ट टीम और ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार इलाके की निगरानी की जा रही है।

दिनभर चला सर्च ऑपरेशन : बुधवार को सुबह से शाम तक वन विभाग की तीन टीमें बायपास रोड, नरापुरा किले की पहाड़ी, तलहटी और आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की खोज में लगी रहीं। इस अभियान में 70 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

पदचिह्नों से मौजूदगी की पुष्टि : वन विभाग को किले की दिशा में तेंदुए के पदचिह्न मिले हैं। इन्हीं निशानों के आधार पर टीम आगे की सर्चिंग कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि टक्कर के बाद तेंदुआ उसी तरफ भागा था।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर : सर्च अभियान में एसडीओ सुधीर पटले, रेंजर प्रवेश पाटीदार सहित पूर्व और पश्चिम रेंज के वनकर्मी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन से ऊंचाई वाले हिस्सों और झाड़ियों में मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।

गंभीर घायल होने की आशंका कम : प्राथमिक आकलन में वन विभाग का मानना है कि वाहन की टक्कर से तेंदुआ गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होगा और संभवतः किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा है। इसके बावजूद उसकी सुरक्षा और आम लोगों की सतर्कता को देखते हुए तलाश जारी रखी गई है।

आवारा कुत्ते ने बाइक सवार पर किया हमला बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर से टकराया

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर में आवारा कुत्ते के हमले से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात बसारी क्षेत्र के पास एक बाइक सवार पर कुत्ते ने हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में युवक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान 48 वर्षीय भागीरथ यादव के रूप में हुई है। वो देर रात घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक एक कुत्ता बाइक के सामने आ गया और हमला कर दिया। संतुलन बिगड़ते ही बाइक डिवाइडर से टकराई और भागीरथ सड़क पर गिर पड़े। उनके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं।

जिला अस्पताल में इलाज जारी : परिजनों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। भागीरथ के भतीजे शिवम यादव ने बताया कि हमला इतना अचानक था कि बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

कुत्तों के हमले के मामले बढ़े : स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों और मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में जानवरों के हमले और काटने के मामले बढ़े हैं।

स्पिनरों के खिलाफ अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से निराश नहीं हूं: हैरी ब्रूक

मुंबई, एजेंसी। वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के स्पिनरों ने परेशान किया। स्पिनर ही मुख्य रूप से इंग्लैंड की हार का कारण रहे, लेकिन हैरी ब्रूक ने इस बात को मानने से इनकार किया कि वह टीम के स्पिन के खिलाफ खेलने के तरीके से निराश हैं। मैच के बाद हैरी ब्रूक ने कहा, ÷मैं अपने बल्लेबाजों के स्पिन के खिलाफ खेलने के तरीके से निराश नहीं हूं। हम वापस जाकर इस पर सोचेंगे और कुछ दिनों में फिर से खेलेंगे।÷ हैरी ब्रूक खुद भी स्पिनर का शिकार बने थे। उन्हें गुडाकेश मोती ने अपनी ही गेंद पर कैच

आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। हैरी ब्रूक के अलावा, जोस बटलर, जैकब बेथल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, और जेमी ओवरटन स्पिन का शिकार बने।

वेस्टइंडीज की जीत में उनके स्पिनरों की अहम भूमिका रही। स्पिनरों के सामने अंग्रेज बल्लेबाजों के बल्ले उठे जैसे उठे ही नहीं। वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाजों ने 12 ओवर फेंके और 6 विकेट आपस में बांटे।

गुडाकेश मोती श्रेष्ठ रहे। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। रोस्टन चेज ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और अकिल हुसैन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिए। इन तीनों स्पिनरों ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाया और दबाव में इंग्लैंड लगातार अपनी विकेट खोती चली गई।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। शरफेन रदरफोर्ड के 42 गेंद पर बनाए नाबाद 76 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 196 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सैम करन के 30 गेंद पर बनाए नाबाद 43 रन की पारी के बावजूद 19 ओवर में 166 रन पर सिमट गई और 30 रन से मैच हार गई। इंग्लैंड ने नेपाल के खिलाफ अपना पहला मुकाबला मुश्किल से जीता था। वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद इंग्लैंड की तैयारियों पर सवालिया निशान है।

टी20 विश्व कप: मोहम्मद नबी पर आईसीसी का एक्शन, मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा

अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी पर बुधवार को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के मैच के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। नबी को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 को तोड़ने का दोषी पाया गया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने से जुड़ा है। जुर्माने के अलावा नबी के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है। पिछले 24 महीने में उनकी यह पहली गलती थी।

यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर की शुरुआत में हुई, जब नबी की अंपायरों के साथ गेंदबाज लुंगी एनगिडी के कलाई बैंड को लेकर लंबी बहस हुई।

नबी ने अपनी गलती मान ली है और एमिरेट्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल ऑफ मैच रेफरी के डेविड गिल्बर्ट की सजा भी मान ली है। इसलिए आईसीसी द्वारा औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी।

ऑन-फील्ड अंपायर जयरामन मदनगोपाल और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, थर्ड अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर के.एन. अनंथापद्मनाभन ने नबी पर आरोप लगाए थे। लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम आधिकारिक फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं।

अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेहद रोमांचक मैच खेला गया था जिसका परिणाम दो सुपरओवर के बाद निकला था। निर्धारित समय में टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे। अफगानिस्तान भी 19.4 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। इसके बाद हुए पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने भी 17 रन बनाए और मैच दूसरे सुपर ओवर में पहुंच गया। इसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 23 रन बनाए। 24 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी अफगानिस्तान ने पहले 2 गेंदों में बिना किसी रन के मोहम्मद नबी का विकेट गंवा दिया।

दासुन शनाका ने अपना रिकॉर्ड बेहतर किया, श्रीलंका के लिए टी20 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया

कैंडी, एजेंसी। टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका की कप्तानी कर रहे ऑलराउंडर दासुन शनाका अपने प्रदर्शन से कभी-कभी हैरान करते हैं। गुरुवार को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी शनाका ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न सिर्फ घरेलू दर्शकों को हैरान किया बल्कि रोमांचित करते हुए श्रीलंका को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शनाका पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उस समय तक श्रीलंका का स्कोर 13.3 ओवर में 136 था। यहां पर श्रीलंका को एक विस्फोटक पारी की जरूरत थी जो टीम को सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा सके। शनाका ने जिम्मेदारी उठाई और महज 19 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से अर्धशतक लगा दिया। अंतरराष्ट्रीय टी20 में श्रीलंका की तरफ से यह सबसे तेज अर्धशतक है। पूर्व में भी श्रीलंका की तरफ से सबसे तेज टी20 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी शनाका के नाम ही था। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने 2023 में पुणे में भारत के खिलाफ 20 गेंद पर अर्धशतक लगाया था।

टी20 विश्व कप: श्रीलंका की बड़ी जीत, ओमान को 105 रन से हराया

कैंडी, एजेंसी। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी के मुकाबले में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से हरा दिया। श्रीलंका की यह दूसरी जीत है। 226 रन के बड़े लक्ष्य के दबाव में ओमान की बल्लेबाजी बिखर गई। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 12 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हम्माद मिर्जा भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नदीम और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए वसीम अली ने क्रीज पर रुकने का साहस दिखाया और चौथे विकेट के लिए पारी की सबसे बड़ी 42 रन की साझेदारी की। वसीम 20 गेंद पर 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। नदीम 56 गेंद में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज दो अंकों में प्रवेश नहीं कर सका।

ओमान 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना सकी और 105

रन के बड़े अंतर से मैच हार गई।

दुश्मंथा चमीरा ने 2 ओवर में 19 रन देकर 2, महिश तिक्षाणा ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2, दुनिथ वेलालागे ने 4 ओवर में 17 रन देकर 1, दुशन हेमंथा ने 4 ओवर में 45 रन देकर 1, कामिंदु मेंडिस ने 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिए।

इसके पहले ओमान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने खराब शुरुआत के बावजूद 5 विकेट पर 225 रन बनाए थे। श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने मात्र 19 गेंद पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली। अंतरराष्ट्रीय टी20 में श्रीलंका की तरफ से यह सबसे तेज अर्धशतक है। शनाका के अलावा, पवन रथनायके ने 28 गेंद पर 1 छक्का और 8 चौकों की मदद से 60 रन और कुसाल मेंडिस ने भी 45 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली।

वनडे विश्व कप 2027 सिर्फ खेलना नहीं, देश के लिए जीतना चाहता हूं: रोहित शर्मा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाया, लेकिन उनके दिल में विश्व कप 2023 का खिताब न जीत पाने का गम अभी भी जिंदा है। रोहित उस कसक को मिटाने के लिए अगला वनडे विश्व कप खेलने और जीतने के प्रति दृढ़संकल्पित हैं। रोहित शर्मा ने बुधवार को एक आईसीसी इवेंट में कहा, ÷वह सिर्फ वनडे विश्व कप 2027 खेलना नहीं चाहते हैं, बल्कि 2023 में अहमदाबाद में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब हैं।÷ पूर्व कप्तान ने कहा, ÷मैं 50-ओवर का विश्व कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं। उस समय कोई टी20 विश्व कप नहीं था, कोई आईपीएल नहीं था। वह क्रिकेट का सबसे ऊंचा स्तर था, जो हर चार साल में होता था। इसलिए, बेताबी थी। उस एक ट्रॉफी का इतना ज्यादा बोझ था। मैं सच में वह ट्रॉफी चाहता हूं, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करने और उसे पाने के

लिए अपनी पूरी ताकत और काबिलियत से सब कुछ करने की कोशिश करूंगा। मैं वहां जाकर अपने देश के लिए विश्व कप जीतना चाहता हूं। टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा की उम्र और फिटनेस की वजह से 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर सवाल था। पिछले 6 महीने में रोहित ने अपनी फिटनेस पर काम किया और अपना वजन कम किया है। साथ ही उनकी बल्लेबाजी में भी जोरदार बदलाव दिखा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनका बल्ला बेशक नहीं चला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से रोमांचित किया था। फिटनेस और फॉर्म के प्रति रोहित की सजगता देखते हुए विश्व कप 2027 को लेकर उनके समर्पण का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौजूदा समय में वनडे फॉर्मेट के बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों में से रोहित शर्मा ने 282 वनडे की 274 पारियों में 33 शतक और 61 अर्धशतक की मदद से 11,577 रन बनाए हैं।

वरुण सिंह भाटी: पैरालंपिक में देश के लिए जीता पदक, 6 महीने की उम्र में हुए थे पोलियो का शिकार

नई दिल्ली, एजेंसी। वरुण सिंह भाटी का नाम देश के श्रेष्ठ पैरा एथलीटों में लिया जाता है। वह ऊंची कूद में देश को पैरालंपिक में पदक दिला चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता का सफर वरुण के लिए आसान नहीं था, लेकिन अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अपना रास्ता बनाया है। वरुण सिंह भाटी का जन्म 13 फरवरी 1995 को नोएडा में हुआ था। महज छह महीने की उम्र में पोलियोमाइलाइटिस का शिकार होने के बाद उनके एक पैर में स्थायी विकलांगता आ गई। गलत दवा की वजह से उनकी परेशानी और बढ़ गई। बचपन में शारीरिक रूप से मिले इस झटके के बावजूद वरुण के परिवार ने उन्हें कभी कमजोर और हतोत्साहित नहीं होने दिया और हमेशा उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही वरुण को खेलों में रुचि थी। बास्केटबॉल उनका पसंदीदा खेल था, लेकिन बाद में उन्होंने ऊंची कूद में बेहतर करने का लक्ष्य बनाया।

उन्होंने सामान्य एथलीटों के साथ अभ्यास करना शुरू किया ताकि उन्हें बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। पूर्व राष्ट्रीय एथलीट सत्यनारायण की कोचिंग में उनके करियर को नई उड़ान मिली। गोस्पोर्ट्स फाउंडेशन के पैरा चैंपियंस प्रोग्राम से मिले समर्थन ने भी उनके सफर को मजबूती दी।

टी42 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले वरुण ने 2012 में 1.60 मीटर की छलांग के साथ लंदन पैरालिंपिक के लिए 'ए' क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया था, हालांकि सीमित स्लॉट के कारण वे उस संस्करण में हिस्सा नहीं ले सके। इसके बाद उन्होंने 2014 एशियन पैरा गेम्स में भाग लिया और उसी साल चाइना ओपन में स्वर्ण पदक जीता।

2016 उनके करियर के लिए शानदार था। आईपीसी एशिया-ओशिनिया चैंपियनशिप में 1.82 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने स्वर्ण और एशियन रिकॉर्ड अपने नाम किया। रियो पैरालिंपिक 2016 में 1.86 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ उन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2018 एशियन पैरा गेम्स में 1.82 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया। उनके बेहतरीन खेल और सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 29 अगस्त 2018 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था।

दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान मैच विश्व कप इतिहास के श्रेष्ठ मैचों में से एक था: इरफान पठान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले को विश्व कप इतिहास के श्रेष्ठ मैचों में से एक बताया। इरफान पठान ने जियोहॉटस्टार पर कहा, ÷यह इस विश्व कप के सबसे अच्छे मैचों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं। असल में, यह विश्व कप इतिहास के सबसे अच्छे मैचों में से एक था, आसानी से शीर्ष पांच में। दो सुपर ओवर और पूरे समय जबरदस्त ड्रामा। नो-बॉल, फ्री हिट, रन-आउट, मिस्ड यॉर्कर, सब कुछ था जो आप चाह सकते थे।÷ पठान ने कहा, ÷गेंदबाजों ने दबाव में यॉर्कर फेंकने की कोशिश की और चूक गए, जो सबके साथ होता है। जब उन्होंने पेस का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने रन बनाए। जब उन्होंने धीमी गेंद फेंकी, तो उन्होंने मुश्किल खड़ी की और विकेट लिए। दूसरे सुपर ओवर में केशव महाराज की आखिरी गेंद बहुत बढ़िया थी। वह गुरबाज से दूर रहे, वाइड लाइन पर गेंदबाजी की, और

पहले वाइड गेंद फेंकने के बाद खुद को संभाला। इससे उनकी क्लास का पता चलता है। सच में एक रोमांचक मुकाबला था। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मैच रोमांचक रहा था। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे। अफगानिस्तान भी 19.4 ओवर में 187 रन पर सिमट गई। इसके बाद पहला सुपर ओवर हुआ जिसमें अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर 17 कर दिया। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ। इसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 23 रन बनाए। पहले 2 गेंदों में बिना किसी रन के मोहम्मद नबी का विकेट गंवाने के बाद अफगानिस्तान को अगले 4 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज ने केशव महाराज को लगातार 3 छक्के लगाए। इसके बाद केशव ने वाइड फेंकी। आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। दोनों टीमों की जीत-हार के साथ एक और सुपर ओवर की संभावना थी।

जर्मन कप: बायर्न ने लीपजिग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

बर्लिन, एजेंसी। बायर्न म्यूनिख ने 2020 के बाद पहली बार जर्मन कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टरफाइनल में आरबी लीपजिग को 2-0 से हराकर बायर्न ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों गोल दूसरे हाफ में आए। लीपजिग ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। क्रिस्टोफ बॉमगार्टनर ने चौथे मिनट में गोल भी कर दिया था, लेकिन वीएआर समीक्षा के बाद इसे ऑफसाइड करार दिया गया। इसके बाद बायर्न ने धीरे-धीरे खेल पर पकड़ बनानी शुरू की। हैरी केन ने शुरुआती मिनटों में गोलकीपर मार्टेन वेंडेवोर्ड्ट को कठिन बचाव करने पर मजबूर किया, जबकि 11वें मिनट में कैस्टेलो लुकेबा ने रिबाउंड पर संभावित गोल को लाइन से हटाकर टीम को राहत दी। पहले हाफ के मध्य में बायर्न ने दबाव बढ़ाया। लुइस डियाज और केन ने करीब से गोल करने की कोशिश की, लेकिन लीपजिग का डिफेंस मजबूती से डटा रहा। एक विवादित क्षण तब आया जब जोसिप स्टैनिसिक ने एंटोनियो नुसा को पेनल्टी बॉक्स के बाहर गिराया, पर

रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोलरहित रहीं।

दूसरे हाफ में मुकाबला संतुलित रहा, लेकिन 64वें मिनट में निर्णायक मोड़ आया। लीपजिग के गोलकीपर वेंडेवोर्ड्ट स्टैनिसिक को चैलेंज करते हुए फिसल गए और बायर्न को पेनल्टी मिल गई। हैरी केन ने शांतचित्त होकर पेनल्टी को गोल में बदला और टीम को बढ़त दिलाई। इसके तीन मिनट बाद ही लुइस डियाज ने 67वें मिनट में दूसरा गोल दागकर बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद बायर्न ने खेल पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और लीपजिग को वापसी का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ बायर्न सेमीफाइनल में बायर लेवरकुसेन, स्टटगार्ट और फ्रीबर्ग के साथ शामिल हो गया है। अंतिम चार के लिए ड्रॉ 22 फरवरी को होगा। मैच के बाद लीपजिग के चेयरमैन ओलिवर मिंट्जलाफ ने बायर्न को बधाई देते हुए कहा कि उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भविष्य में बायर्न को हराने के लिए और मेहनत की जरूरत होगी।

राजिम कुंभ कल्प में दर्शनीय स्थलों की दी जा रही डिजिटल जानकारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजिम कुंभ कल्प मेला में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल मेलार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें संस्कृति, पर्यटन, पुरातत्व एवं धर्मस्व विभाग का स्टॉल विशेष रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ आकर्षित कर रहा है। बड़ी संख्या में आगंतुक यहां पहुंचकर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्टॉल में विशाल एलईडी स्क्रीन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का आकर्षक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे मेलार्थी रुचि के साथ देख रहे हैं। इसके साथ ही राजिम, डोंगरगढ़, सोनाखान, चंद्रखुरी, रायपुर, दंतेवाड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी वाली बुकलेट्स निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। इन बुकलेट्स में संबंधित स्थलों की दूरी, आसपास के प्रमुख आकर्षण, आवास एवं ठहरने की सुविधाएं तथा यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां विस्तारपूर्वक दी गई हैं। विशेष रूप से प्रत्येक बुकलेट में क्यूआर कोड प्रदान किया गया है, जिसे स्कैन कर मेलार्थी अपने मोबाइल पर संबंधित पर्यटन स्थल की विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी तुरंत प्राप्त कर रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प में एक ही स्थान पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की समग्र एवं उपयोगी जानकारी मिलने पर लोग इस अभिनव पहल को सराह रहे हैं।

रैंप योजना अंतर्गत बुनकर केन्द्र लखोली में 32 महिला उद्यमियों को मिला सेक्टर स्पेसिफिक प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। केन्द्र सरकार की रैंप (RAMP) योजना अंतर्गत बुनकर केन्द्र लखोली में हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी 32 महिला उद्यमियों के लिए तीन दिवसीय सेक्टर स्पेसिफिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शासन की उद्यमिता प्रोत्साहन पहल के तहत सीएसआईडीसी रायपुर के मार्गदर्शन में चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण संपन्न कराया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना तथा प्रतिभागियों को तकनीकी एवं व्यवहारिक दक्षता प्रदान करना था। प्रथम दिवस प्रतिभागियों की वर्तमान गतिविधियों एवं चुनौतियों पर संवाद कर मास्टर ट्रेनर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। द्वितीय दिवस केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं, सब्सिडी, ईडीपी, कौशल विकास, विपणन रणनीतियों एवं उद्यम पंजीयन पर जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से दंतेवाड़ा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के अंतर्गत ग्रामीणों की आजीविका सुदृढ़ करने की दिशा में मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत, पर्यावरण-अनुकूल एवं स्थायी आजीविका गतिविधि से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के तहत चयनित किसानों को 6-6 मधुमक्खी बक्से मधुमक्खियों सहित, आवश्यक उपकरण तथा तीन दिवसीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग हंबल बी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। परियोजना की अधिकांश राशि जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से वहन की जा रही है, जबकि हितग्राहियों से स्वामित्व की भावना विकसित करने हेतु नाममात्र का अंशदान लिया जा रहा है। परियोजना का प्रारंभिक क्रियान्वयन गीदम विकासखंड में किया जा रहा है। प्रथम चरण में बिंजाम, सियानार, समलूर, झोड़ियाबाड़म, बड़े कारली, कारली, घोटपाल, कासौली एवं कुतुलनार ग्रामों के कुल 100 किसानों को वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इससे प्रत्येक हितग्राही को शहद उत्पादन से प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में जिला समन्वयक पदों पर भर्ती

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों तक सरकारी एवं निजी डिजिटल सेवाओं की सहज पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित जिलों में जिला समन्वयक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सीएससी द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह नियुक्तियाँ दुर्ग, कांकेर, जशपुर एवं कोरबा जिलों के लिए की जाएंगी। प्रत्येक जिले के लिए पृथक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा अभ्यर्थी को उसी जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। जिला समन्वयक जिले में संचालित सीएससी ई-गवर्नेंस सेवाओं के संचालन, निगरानी एवं विस्तार के लिए उत्तरदायी होंगे। वे जिला प्रशासन, विभिन्न शासकीय विभागों, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों, फील्ड स्टाफ तथा वीएलई नेटवर्क के साथ समन्वय स्थापित कर डिजिटल सेवाओं एवं योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सेवा गुणवत्ता, लक्ष्य प्राप्ति तथा नियमित रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी। इस पद हेतु अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है।

लक्ष्मी राजवाड़े गृह ग्राम बीरपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा में शामिल हुई

कलश यात्रा एवं वैदिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ धार्मिक आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने गृह ग्राम बीरपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में सहभागिता कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।

प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत प्रातः राम मंदिर, पासंग नाला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कलश यात्रा शिव मंदिर परिसर तक पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधानपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं रात्रि में भजन-कीर्तन के माध्यम से भक्तिमय वातावरण बना रहा।

इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में आपसी सौहार्द, एकता और आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने ग्रामवासियों को इस सफल एवं भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि नवनिर्मित शिव मंदिर ग्राम बीरपुर में आस्था और सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, बाबूलाल अग्रवाल, अनिल सिंह मेजर, भीमसेन अग्रवाल, अजय गोयल सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कर एवं शास्ति बकाया मामले में पांच वाहन किए जब्त

एक सप्ताह में भुगतान न होने पर नीलामी की होगी कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 15 के अंतर्गत परिवहन विभाग जशपुर द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज बकाया होने के कारण पांच वाहनों को जब्त किया गया है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्त किए गए वाहनों में भगत बस (सीजी 14 जी 0338), वाहन क्रमांक सीजी 14 एमएल 0238, चिस्ती बस (सीजी 14 जी 0197), हीराहरी बस (सीजी 14 एमजी 9461) तथा बस क्रमांक सीजी 14 एमएच 6739 शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति की जा सकती है।

धारा के तहत संबंधित वाहन एवं उसके उपसाधनों को कुर्क एवं जब्त कर नीलाम किए जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमानुसार वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा कर अदायगी सुनिश्चित करने हेतु आगे भी अभियान जारी रहेगा।

मधु वर्मा का घर का सपना हुआ साकार प्रधानमंत्री आवास योजना से

कठिन संघर्षों के बाद मिला पक्का आशियाना, जीवन में जगी नई उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य पात्र शहरी और ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो मुख्य घटक हैं पीएमएवाई-शहरी जिनके तहत बुनियादी सुविधाओं (पानी, बिजली, शौचालय) से लैस घर प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 ने जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियों की नई किरण जगाई है। इसका जीवंत उदाहरण राजनांदगांव नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक-3 मोतीपुर में निवासरत मधु वर्मा हैं, जिनका वर्षों पुराना पक्का घर का सपना अब साकार हो गया है। पति के निधन के बाद परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी मधु वर्मा के कंधों पर आ गई थी। दो बेटियों के पालन-पोषण हेतु वे एक निजी स्कूल में रसोईया के रूप में कार्य कर परिवार का भरण-पोषण कर रही थीं। किराए के मकान में रहते हुए आर्थिक तंगी और असुरक्षा की भावना उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। स्कूल में छुट्टियों के दौरान आय कम होने से समय पर किराया चुकाने की चिंता हमेशा बनी रहती थी। मधु वर्मा बताती हैं कि उन्हें अक्सर यह भय सताता था कि कहीं किराया समय पर न दे पाने की स्थिति में मकान मालिक मकान खाली करने के लिए न कह दिया जाए। ऐसे हालात में अपने पक्के घर का सपना केवल कल्पना तक ही सीमित था।

इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी सुजाता को एक निजी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में रोजगार मिला। मां-बेटी ने मिलकर थोड़ी-थोड़ी बचत की और अंततः एक छोटा सा भूखंड खरीदा। इसके बाद मधु वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवेदन किया। कुछ ही दिनों में उनके आवास निर्माण की स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिलने के पश्चात पूरे परिवार ने उत्साह और उमंग के साथ अपने सपनों के घर का निर्माण प्रारंभ किया। इंजीनियर के कुशल मार्गदर्शन में शीघ्र ही एक सुंदर, आकर्षक एवं सर्वसुविधायुक्त पक्के मकान का निर्माण पूर्ण हुआ। आज मधु वर्मा टाइल्स से सजे अपने पक्के घर में रहते हुए गर्व और संतोष का अनुभव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल उन्हें घर दिया, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास और नई उम्मीद भी जगाई है। अपने सपनों का घर मिलने पर मधु वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है।

राजिम कुंभ कल्प में आधुनिक खेती का संदेश

उद्यानिकी स्टॉल में पाम फल बना आकर्षण का केंद्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजिम कुंभ कल्प मेला में इस वर्ष कृषि एवं उद्यानिकी विभाग का स्टॉल किसानों एवं मेला दर्शनार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तिलहन, दलहन तथा सब्जी फसलों की प्रदर्शनी के साथ पाम (ऑयल पाम) की खेती संबंधी जानकारी लोगों में खासा उत्साह जगा रही है। पाम के फल को पहली बार नजदीक से देखकर अनेक लोग आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसके व्यावसायिक लाभ के संबंध में जानकारी लेते नजर आए।

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ने बताया कि पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर विभिन्न मदों में अनुदान प्रदान किया जा रहा है। फेंसिंग के लिए 54,485 रुपये, अंतरवर्ती फसल हेतु 10,250 रुपये, रखरखाव के लिए 6,550 रुपये तथा ड्रिप सिंचाई पर 22,765 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में छुरा विकासखंड में लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में पाम की खेती की जा रही है। पाम के पौधे कंपनियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उत्पादित फल को कंपनी 17 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर क्रय करती है।

पौधरोपण के लगभग चार वर्ष बाद फल लगना प्रारंभ होता है, अतः किसान प्रारंभिक वर्षों में दलहन, तिलहन एवं सब्जियों की अंतरवर्ती खेती कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। पाम से खाद्य तेल का उत्पादन होता है, जिससे इसकी बाजार में निरंतर मांग बनी रहती है।

स्टॉल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली तथा फलदार पौधों के रोपण पर उपलब्ध अनुदान के संबंध में किसानों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। यह पहल किसानों को आधुनिक एवं लाभकारी खेती की ओर प्रेरित कर रही है।

दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल

शासन की स्वरोजगार योजना से हेमंत साहू बने आत्मनिर्भर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाएँ जमीनी स्तर पर सकारात्मक और प्रभावी परिणाम दे रही हैं। इसी कड़ी में जिला मोहलाङ्कमानपुरङ्कअंबागढ़ चौकी के विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम कौड़ीकसा निवासी अस्थिबाधित दिव्यांग हेमंत कुमार साहू की कहानी एक प्रेरणास्पद उदाहरण के रूप में सामने आई है। शासन की स्वरोजगार मूलक ऋण योजना का लाभ लेकर उन्होंने आत्मनिर्भरता की सशक्त पहचान स्थापित की है।

पूर्व में हेमंत साहू के पास आजीविका का कोई स्थायी साधन उपलब्ध नहीं था। सीमित संसाधनों एवं पारिवारिक दायित्वों के कारण जीवनयापन में निरंतर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं। इसी दौरान समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें दिव्यांगजनों के लिए संचालित स्वरोजगार ऋण योजना की जानकारी प्राप्त हुई। योजना के अंतर्गत आवेदन उपरांत शासन द्वारा उन्हें 95 हजार रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई। प्राप्त आर्थिक सहायता का समुचित उपयोग करते हुए साहू द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय की स्थापना की गई।

मछली पालन और खेतों की सिंचाई का आधार बनेगी आजीविका डबरी

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के दिव्यांग अंधरू बैगा के लिए मनरेगा की पहल बनी वरदान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकें और अपने परिवार के भरण पोषण के साथ गांव की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत लोखान अंतर्गत ग्राम कमराखोल में विशेष पिछड़ी जनजाति के दिव्यांग हितग्राही अंधरू बैगा के लिए मनरेगा के तहत निर्मित की जा रही आजीविका डबरी उनके सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव साबित होगी।ग्राम सभा में मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को आजीविका डबरी निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। इसके लाभों से प्रभावित होकर श्री अंधरू बैगा ने अपने लिए डबरी निर्माण की मांग रखी। वे पूर्व से मनरेगा के तहत पंजीकृत होकर कार्य कर रहे हैं। ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर लगभग 1.05 लाख रुपये की लागत से उनके लिए आजीविका डबरी स्वीकृत की गई।

डबरी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें अब तक 574 मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। स्वयं हितग्राही श्री अंधरू बैगा को 36 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ तथा 9 हजार 360 रुपये की मजदूरी राशि उनके बैंक खाते में भुगतान की गई है। लगभग 20 गुणा 20 गुणा 3 मीटर आकार की यह डबरी पूर्ण होने पर करीब 894 घन मीटर जल संचयन क्षमता प्रदान करेगी। इससे मछली पालन, बाड़ी विकास और खेतों की सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि से आसपास के क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा अभिसरण के माध्यम से मछली बीज, आवश्यक दवाइयां, जाल तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही डबरी के मेढ़ और आसपास की भूमि में नमी रहने से सब्जी उत्पादन के नए अवसर भी विकसित होंगे। निकटतम बाजार कुई में उत्पादों की आसान बिक्री से हितग्राही की आय में निरंतर वृद्धि संभव होगी।

हितग्राही अंधरू बैगा ने बताया कि आजीविका डबरी बनने से उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा। मछली पालन और सब्जी उत्पादन के माध्यम से उन्हें स्थायी आय का साधन मिलेगा और रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो रही है और अब उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सुखद दिखाई दे रहा है। शासन की योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए: आबकारी आयुक्त

मदिरा एवं मादक पदार्थों के अवैध संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। आबकारी विभाग की सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने आज नवा रायपुर स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलों, उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए।

सचिव सह आबकारी आयुक्त शंगीता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया किया मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं के मांग के अनुरूप मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो। उन्होंने अधिकारियों को मदिरा दुकानों में नियम और अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।

शंगीता ने बैठक में राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए जिन जिलों ने जनवरी माह तक लक्ष्य की प्राप्ति की है, उन्हें सतत् कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों को इसके कारणों की दुकानवार समीक्षा कर कमी की पूर्ति हेतु विस्तृत कार्य-योजना बनाकर तत्परता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को इस बात की स्पष्ट हिदायत दी कि मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट न होने पाए। इसके लिए सभी जिला अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन आकस्मिक निरीक्षण करने और वहां पाई गई अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई और दोषी कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दुकानों में पेटीएम या अन्य कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए।

सचिव सह आयुक्त ने प्रदेश में संचालित बारों, क्लबों, होटलों और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और विक्रय पर सख्त नियंत्रण रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए।

राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा कर्मचारियों के पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री पदुम सिंह एल्मा, विशेष सचिव आबकारी विभाग श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय व जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।

टोहेमेटा में एनीकट निर्माण हेतु 3.56 करोड़ की स्वीकृति

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्य शासन द्वारा गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के ग्राम टोहेमेटा में एनीकट निर्माण कार्य के लिए 356.36 लाख (तीन करोड़ छप्पन लाख छत्तीस हजार रूपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित एनीकट निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल उपलब्धता तथा भू-जल संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा और कृषकों द्वारा लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी।

परियोजना को वित्त एवं योजना विभाग की समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने के पश्चात विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तथा प्रचलित वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित कर पूर्ण किया जाए।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा